04 - दलित राजनीति और सत्ता का षड्यंत्र

05 -अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारत और बदलती धारणाएं

A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 08 अक्टूबर, 2025

06 - नपा को जिला प्रशासन से मिलेगी जमीन, मंजूरी मिलते ही शुरू होगा काम

07 - पत्रकारों को चरणबद्ध ढंग से गढ़ते थे मामाजी

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 349, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारतीय टैलेंट को अमेरिका से वापस बुलाना इतना मुश्किल क्यों?

निखिल इनामदार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एच-1बी वीज़ा की फ़ीस कई गुना बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी। कहा जा रहा है कि भारत के पॉलिसी मेकर अब काबिल भारतीयों को वापस अपने देश बुलाने की कोशिश में लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क़रीबी एक अफसर ने हाल ही में कहा है कि सरकार विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को वापस आने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

वहीं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि एच-1बी वीज़ा हमेशा से मेजबान देश के हितों को ही पूरा करता आया है। इसलिए, वीज़ा फ़ीस में यह बढ़ोतरी भारत के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि इससे भारत की वैश्विक प्रतिभा को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ेगी। इन सब बातों का सार यह है कि अब भारत के पास 'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' यानी विदेशों में बसे प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस लाकर अपने देश में काम करने का माहौल बनाने का अच्छा अवसर है। ख़ासकर टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और इनोवेशन से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ में।

हालांकि कुछ उदाहरण बताते हैं कि अमेरिका में सख़्त होती इमिग्रेशन नीतियों के कारण कुछ भारतीय अब वाकई वापस आने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हज़ारों लोगों को अमेरिका छोड़कर बेंगलुरु (भारत) लौटने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। नितिन हसन उन कुछ भारतीयों में से एक हैं जो पिछले 20 साल से अमेरिका में बसे हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़ा क़दम उठाते हुए पिछले साल भारत लौटने का फ़ैसला किया। उनके लिए यह फ़ैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने मेटा में अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़ दी ताकि स्टार्टअप की अनिश्चित दुनिया में क़दम रख सकें। हसन ने कहा, 'मैं हमेशा से कुछ अपना शुरू करना चाहता था, लेकिन अमेरिका में मेरी इमिग्रेशन स्थिति ने उस आज़ादी को सीमित कर दिया था।'

भारत लौटने के बाद, हसन ने दो स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिनमें से एक है बी2आई (बैक टू इंडिया)। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो अमेरिका में बसे भारतीयों को वापस लौटने की भावनात्मक, आर्थिक और पेशेवर चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों में आए बदलावों के चलते भारत लौटने की इच्छा रखने वालों की पूछताछ में तेज़ी आई है, और एच-1बी वीज़ा विवाद ने इसे और बढ़ा दिया है।

हसन ने कहा, 'अब कई पेशेवर मान चुके हैं कि उन्हें ग्रीन कार्ड शायद कभी नहीं मिलेगा, और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से बी2आई पर आने वाली पूछताछ लगभग तीन गुना बढ़ गई है। सिर्फ़ पिछले छह महीनों में ही दो सौ से ज़्यादा एनआरआई (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) भारत वापसी के विकल्पों पर चर्चा के लिए हमसे जुड़ चुके हैं।'

अमेरिकी विश्वविद्यालयों से भारतीय प्रतिभा की तलाश करने वाली अन्य कंपनियां भी इस बदलते रुझान की पुष्टि करती हैं। बीडीओ एक्जीक्यूटिव सर्च की सीईओ शिवानी देसाई ने बताया, 'इस सीज़न में आइवी लीग विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 30 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे माहौल के कारण अमेरिका में काम कर रहे वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों को अब अपने लंबे करियर को लेकर 'गंभीरता से सोचने' पर मजबूर होना पड़ रहा है।'

देसाई ने कहा, 'हालांकि उनमें से कई अब भी वहीं टिके हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शीर्ष पदों पर बैठे ऐसे अधिकारियों और सीनियर टेक लीडर्स की संख्या बढ़ रही है जो भारत को एक गंभीर विकल्प के रूप में देख रहे हैं।' उनके रवैये में यह बदलाव भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में रिमोट ऑफ़िस के कारण भी हो सकता है। ये कंपनियां लौटने वाले भारतीयों के लिए बेहतर काम के मौके दे रही हैं।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलटन के मुताबिक़, अगर अमेरिका टेक प्रोफ़ेशनल्स के लिए अपने दरवाज़े बंद करता है, तो ये लोग ऑफशोर ऑपरेशन्स की ओर रुख़ कर सकते हैं। ऐसे में जीसीसी प्रतिभाओं के लिए और भी आकर्षक बनते जा रहे हैं, खासतौर पर तब जब ऑनसाइट अवसर लगातार घट रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार और पुस्तक 'सेसेशन ऑफ़ द सक्सेसफुलः द फ़्लाइट आउट ऑफ़ न्यू इंडिया' के लेखक संजय बारू ने भी इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा, 'बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन यानी प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार की ओर से संगठित और गंभीर प्रयास की ज़रूरत होगी, और वर्तमान में यह कमी है। सरकार जिन्हें वापस लाना चाहती है इसके लिए सरकार को सक्रिय रूप से उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी, जिनमें टॉप लेवल के वैज्ञानिक, पेशेवर और उद्यमी शामिल हैं। इसके लिए गंभीर प्रयास की ज़रूरत है और यह पहल सीधे टॉप लेवल से आनी चाहिए।'

उन्होंने कहा कि यही काम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ताकि अंतरिक्ष और न्यूक्लियर तकनीक जैसे क्षेत्रों में टॉप माइंड्स को वापस लाकर भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान बनाए जा सकें। बारू ने कहा, 'उनमें उद्देश्य और राष्ट्रभक्ति की गहरी भावना थी। अब वापस आने के लिए प्रोत्साहन कहां है?' उन्होंने कहा कि इसके उलट, देश में हमेशा से कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो हुनरमंद पेशेवरों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और भारत ने इस चलन को रोकने के बजाय हमेशा जश्न 'मनाया' है। पुल फैक्टर्स में उन देशों की बढ़ती संख्या शामिल है, जो गोल्डन वीज़ा, नागरिकता या इमिग्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से रेज़िडेंसी ऑफर कर रहे हैं।

असल में, जब अमेरिका ने अपने एच1बी वीज़ा नियमों को कड़ा किया, तभी जर्मनी जैसे देशों ने तुरंत कुशल भारतीय प्रवासियों के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए। पुश फैक्टर पुरानी और बड़ी समस्या रही है, जैसे कि ख़राब सरकारी नियम-क़ानून, थकाने वाली नौकरशाही, और ख़राब व्यापारिक माहौल। ऐसे ही कुछ कारणों से पिछले कई सालों से अमीर और ज़्यादा कमाने वाले भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं। हसन कहते हैं कि अगर सरकार सच में विदेशों में बसे भारतीयों को वापस लाने के लिए गंभीर है, तो उन्हें 'कई बाधाओं को एक साथ दूर करने' की दिशा में काम करना होगा। इसमें टैक्स को लेकर आसान क़ानून, स्पेशल स्टार्टअप वीज़ा जैसी योजनाएं और अन्य मौलिक समस्याओं का समाधान शामिल है, जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी और शहरी भीड़भाड़।

मुख्यमंत्री ने किया कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ

प्रदेश में हमने स्थापित की है जवाबदेह शासन व्यवस्था

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी लोक सेवकों से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए प्राण-प्रण से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण के लिए शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर मिशन मोड में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित की है। लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी प्रतिभा, लगन, क्षमता और समर्पण के साथ जनता तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाएँ। हम सब देश और समाज के विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें।

- **समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे विकास और कल्याण की किरण–** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की किरण पहुंचाना है। राज्य सरकार सबके साथ, सबके लिए खड़ी है। जनता में यह विश्वास पैदा करना ही सुशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रदेश में जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें यह जनविश्वास हर हाल में बनाए रखना है।
- **योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से मिले जनता को–** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर मंथन किया जाएगा कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में तैनात अधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान कायम करें। किसी भी ज्वलंत विषय पर पूरी दक्षता और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। स्थानीय जनता, मीडिया और जनप्रतिनिधियों से निरंतर आत्मीय संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परमात्मा ने यदि हमें समाज के लिए काम करने का दायित्व दिया है तो हमें एक विनम्र विद्यार्थी की तरह इस दायित्व का निर्वहन करना ही चाहिए।

गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट की ओर हों अग्रसर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि लोकतंत्र एवं जनकल्याण में हम सबकी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट भूमिका है। फील्ड में तैनात अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस से हम ग्रेट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और हम सभी को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेज़ी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परफॉर्म, रिफार्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में जन सेवा का मंत्र दिया है। आप सभी इस मंत्र को आत्मसात करते विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलेक्टर्स ऐसे जनहितैषी कार्य करें, जो आने वाले समय में जिले की जनता को याद रहें। अपने कार्यकाल का एक-एक क्षण जन-कल्याण में लगाएं और प्रदेश को नई ऊंचाईयों में ले जाएं। उन्होंने कहा कि नवाचार ऐसे हों, जो दीर्घकालिक हों। जिस विभाग से संबंधित नवाचार हो, उसकी पूरी कार्ययोजना विभाग से अनुमोदित हो, जिससे वह नवाचार स्थाई हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है। दाल, मसाले एवं टमाटर उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। गेहूं, मक्का और मिर्च में दूसरे स्थान पर हैं। दुग्ध उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। अब हम विभिन्न प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध कैपिटल बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश में योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक ले जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

2 और बच्चों की मौत, अब तक 16 जानें गईं

मप्र में जहरीले सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

न्यायिक जांच की मांग, ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाए केंद्र

छिंदवाड़ा (नप्र)। जहरीला कफ सिरप पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो और बच्चों की मौत हो गई। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और दो साल की जायुषा यदुवंशी ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 16 पहुंच गया है।

उधर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

इसमें मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए गठित एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश भी दिए जाएं।

साथ ही अलग-अलग राज्यों में ऐसे मामलों में दर्ज सभी एफआईआर एक जगह ट्रांसफर करके पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए।

मध्य प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया है। उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक दिनेश श्रीवास्तव को फूड और ड्रग कंट्रोलर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

सुप्रभात

धूप निकली दिन सुहाने हो गए
चाँद के सब रंग फीके हो गए
इस क़दर रोया हूँ तेरी याद में
आइने आँखों के धुँधले हो गए
हम भला चुप रहने वाले थे कहीं
हाँ मगर हालात ऐसे हो गए
अब तो ख़ुश हो जाएँ अरबाब-ए-हवस
जैसे वो थे हम भी वैसे हो गए
हुस्न अब हंगामा-आरा हो तो हो
इश्क़ के दावे तो झूठे हो गए
ऐ सुकूत-ए-शाम-ए-ग़म ये क्या हुआ
क्या वो सब बीमार अच्छे हो गए
दिल को तेरे ग़म ने फिर आवाज़ दी
कब के बिछड़े फिर इकट्ठे हो गए
आओ 'नासिर' हम भी अपने घर चलें
बंद इस घर के दरीचे हो गए।

– **नासिर काज़मी**

जो भी किया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील ने रखा अपना पक्ष,कहा-डर भी नहीं है

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर कुमार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा– सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से मैं आहत हूं। उनके ऐक्शन (टिप्पणी) पर ये मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ, मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। उन्होंने कहा– यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े-बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए– हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तीन साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है। वहीं, इस घटना पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा–मूर्ति केस में सीजेआई की टिप्पणी गलत पेश की गई।

24,634 करोड़ के 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

● केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला,पीएम मोदी थे मौजूद

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 24,634 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के इटारसी- भोपाल-बीना रूट पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले वडोदरा- रतलाम रूट पर 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। वैष्णव ने बताया , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। भारत के सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेलवे यातायात का 41 फीसदी संभालते हैं, और इन परियोजनाओं से इन कॉरिडोर की क्षमता और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वैष्णव ने कहा कि न प्रोजेक्ट्स से न केवल रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भीड़ कम होगी, समय की बचत होगी और रेलवे सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार होगा। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि इन कॉरिडोर में कम से कम चार लाइनें बनेंगी और जहां संभव होगा, छह लाइनें बनाई जाएंगी। चौथा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच चौथी लाइन है। यह प्रोजेक्ट 237 किमी लंबा है। वैष्णव ने बताया कि आज जिन चार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, वे देश के सात सबसे व्यस्त रेलवे रूट्स का हिस्सा हैं। देश का 41 फीसदी कार्गो और 41 फीसदी पैसेंजर ट्रैफिक इन रूट्स से गुजरता है। रतलाम से वडोदरा वाला हिस्सा दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। इसी तरह भुसावल से वर्धा वाला प्रोजेक्ट मुंबई-हावड़ा रूट पर है। बीना से इटारसी वाला हिस्सा दिल्ली-चेन्नई रूट पर है। गोंदिया से डोंगरगढ़ प्रोजेक्ट मुंबई-हल्दिया लाइन पर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी।

किसानों को हर हाल में मिलेगा सोयाबीन फसल का उचित दाम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की मेहनत का सम्मान दिलाने के लिए उन्हें हर हाल में सोयाबीन फसल का उचित दाम दिलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भावान्तर योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भावमें अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 30 °c
न्यूनतम 25°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 08 अक्टूबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

हरियाणा में सीनियर आईपीएस अफसर ने किया सुसाइड

चंडीगढ़ आवास में खुद को मारी गोली, सुनारिया जेल में थे तैनात

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफीसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने सरकारी आवास (कोठी नंबर 116) पर खुद को गोली मार ली। चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अभी यह सामने नहीं आया है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वाई पूरन कुमार डीजीपी रैंक के अधिकारी थे। 29 सितंबर को ही उनकी ट्रांसफर रोहतक की सुनारिया जेल में हुई थी।

इसी जेल सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमन पी. कुमार भी आईएएस ऑफीसर हैं। वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ 5 अक्टूबर को जापान दौरे पर गई थीं। वह कल शाम को भारत लौटेंगी। करीब 1 साल पहले हरियाणा में 4 बैच (1991, 1996, 1997 और 2005) के अफसरों के प्रमोशन पर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने प्रमोशन के अवैध होने का कारण वित्त विभाग की महज सहमति से गाइडलाइंस को ओवररूल किया जाना बताया।

60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ

साढ़े 4 घंटे तक ईओवी के सवाल-जवाब

मुंबई (एजेंसी)। शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम ने पूछताछ की है। ईओवी की टीम करीब साढ़े 4 घंटे तक एक्ट्रेस से सवाल-जवाब करती रही। उनके अलावा शिल्पा के पति राज कुंद्रा का बयान भी दर्ज किया गया है। उनका नाम भी शिकायत में दर्ज है। अफसरों ने शिल्पा और राज कुंद्रा समेत 5 लोगों के बयान लिए हैं। उनसे पूरे लेन-देन की जानकारी ली गई। ये पूछताछ शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर में हुई थी।

फिलहाल जांच टीम उस कंपनी का ब्योरा निकाल रही है, जिससे उस समय शिल्पा और राज जुड़े हुए थे। इसी मामले में राज से बीते हफ्ते भी पूछताछ हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बेस्ट डील को दीपक कोठारी द्वारा दी गई रकम को बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को बतौर प्रोफेशनल फीस दी जा चुकी थी। अगस्त में मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है। दीपक कोठारी के मुताबिक, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा से हुई थी।

धवल चांदनी में चांदी के सिंहासन पर विराजे बांके बिहारी

● बंसी और मोर मुकुट धारण किया, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर महारास हुआ

मथुरा (एजेंसी)। शरद पूर्णिमा पर ब्रज में अलौकिक छठा बिखरी। यहां के मंदिरों में भगवान को श्वेत पोशाक धारण कराई गई। बांके बिहारी जी ने चंद्रमा की धवल चांदनी में चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। बंसी, मोर मुकुट, कटी कांचनी धारण किए भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन कर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य महारास का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान की छठा अलग ही देखते बन रही थी।

केशवदेव मंदिर परिसर को चंद्र लोक का स्वरूप दिया गया। यहां भगवान के दर्शन कर ऐसा लग रहा था जैसे वह चंद्र वाहन में विराजमान होकर दर्शन दे रहे हों। देश विदेश से आए श्रद्धालु भगवान के चंद्र वाहन में विराजमान स्वरूप के दर्शन कर जय जयकार करने लगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मस्थान के लीला मंच पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायिकाओं गुंजन तिवारी और गुनगुन तिवारी द्वारा गाए गए भजनों पर भक्त झूमने को मजबूर हो गए।

● गोवर्धन तलहटी में गिर्राज जी को अर्पित किए 56 भोग- शरद पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित तलहटी में गिर्राज जी को 56 भोग अर्पित किए गए। चांदनी महल में विराजमान भगवान गोवर्धन नाथ की छवि अलौकिक छठा बिखेर रही थी। बगीचे में विराजमान भगवान गोवर्धन को हजारों किलो सामग्री से बने 56 भोग अर्पित किए गए। शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में भी किया गया। यहां भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ गरुड़ स्तंभ के समीप स्थित मंडप में चांदी से बने चंद्र प्रभा वाहन में विराजमान हुए।

बारिश का सिस्टम कमजोर, लौटेगा मानसून

एमपी से 10 अक्टूबर तक विदाई ; अगले 2 दिन तक हल्की बारिश होगी

भोपाल (नप्र)। अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब मध्यप्रदेश से मानसून विदा होगा। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक, 2 दिन बाद मानसून के लौटने की परिस्थितियां बेहतर है। यानी, 10 से 12 अक्टूबर के बीच प्रदेश से मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। हालांकि, इससे पहले हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है।

बता दें कि पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई थी। भोपाल में 16 साल बाद दो घंटे में ही रिकॉर्ड ढाई इंच पानी गिर गया था। इससे पहले साल 2009 में एक घंटे में 3 इंच पानी गिरा था। मौसम विभाग के अनुसार, हवा में नमी की वजह से प्रदेश के 33 जिलों में अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ था।

6 अक्टूबर को श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नरसिंहपुर, रतलाम, मंदसौर, धार, बड़वानी, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़ और विदिशा जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई थी। इनमें से भोपाल, रायसेन, गुना और हरदा भारी बारिश दर्ज की गई थी।

इसके बाद सोमवार को तेज बारिश का दौर थमा, लेकिन कुछ जिलों में बूंदाबांदी वाला मौसम रहा। भोपाल में दिन में तेज धूप खिली रही, लेकिन शाम को बादल छा गए।

एमपी के पूर्वी हिस्से में एक चक्रवात - मौसम विभाग के अनुसार, एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एक्टिव है। इसकी वजह से हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है। बाकी सिस्टम प्रदेश से काफी दूर है। तीसरे दिन यानी, 9 अक्टूबर को कुछ ही जिलों में बूंदाबांदी या गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। 10 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा।

अब तक 12 जिलों से लौट चुका मानसून - मौसम विभाग के अनुसार, अब तक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा हो चुका है। राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून विदा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की वापसी के लिए अब परिस्थिति अनुकूल होने वाली है। बता दें कि इस साल मानसून ने मध्यप्रदेश में 16 जून को दस्तक दी थी। समय से एक दिन बाद मानसून प्रदेश में एंटर हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो जाता है, लेकिन नया सिस्टम बनने से विदाई की तारीख आगे भी बढ़ सकती है।

क्रेजी मेडिसिन, भूल भुलैया...नॉर्थ-ईस्ट है टारगेट

इंफाल (एजेंसी)। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे संवेदनशील राज्य मणिपुर है। यह वह राज्य है जहां अशांति है। यह उथल-पुथल बीते लगभग दो वर्षों से है। यहां मैतेई बनाम कुकी का मुद्दा हिंसक हुआ और दो वर्गों की लड़ाई ने पूरे राज्य को चपेट में ले लिया। यहां कई लोगों की मौत हुई। ऐसे तमाम वीडियो सामने आए, जिसमें युवाओं ने पथराव, आगजनी और हिंसक वारदातें कीं। मणिपुर की यंग जेनेरेशन अचानक इतनी हिंसक कैसे हो गई। इस मामले में बड़ी साजिश की बू आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में एक ड्रग्स का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पुलिस और सेना इस ड्रग्स की खेप आए दिन जब्त कर रही है लेकिन यह सिलसिला नहीं थम रहा है। सूत्रों की मानें तो यही वह ड्रग है, जो युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रही है। यह ड्रग्स बहुत खतरनाक है। मणिपुर के इंफाल जिले में सोमवार को दो संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध तस्करों के पास से दो किलोग्राम वर्ल्ड इज योर्स' नाम की ड्रग्स जब्त की गई। इसे डब्ल्यूवाई या याबा नाम से भी जानते हैं। जिन दो ड्रग्स तस्करों को पकड़ा, उनके नाम मोहम्मद इथम खान और राजू खान हैं।

● भारत के खिलाफ अब हो रही है खतरनाक साजिश

● याबा ड्रग्स जो कर रही है लोगों को जलाने का काम

विंध्याचल और इटारसी-प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस का माधवनगर में अस्थाई ठहराव

सतगुरु बाबा नारायण शाहजी की बरसी पर रेलवे का निर्णय

भोपाल (नप्र)। त्यौहारों और मेलों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे लगातार विशेष इंतजाम करता है। इसी क्रम में भोपाल रेल मंडल ने सतगुरु बाबा नारायण शाहजी की बरसी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों को राहत देते हुए दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का माधवनगर स्टेशन पर अस्थाई ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह ठहराव जबलपुर मंडल के निवाड़ा-कटनी रेलखंड स्थित माधवनगर स्टेशन पर 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 तक, यानी चार दिनों के लिए रहेगा। इस अवधि में ट्रेनें एक मिनट के लिए माधवनगर स्टेशन पर रुकेंगी।

अस्थाई ठहराव मिलने वाली ट्रेनें

11273/11274 इटारसी-प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस
11271/11272 इटारसी-भोपाल-इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

यूएन में भारत बोला पाकिस्तान अपने ही लोगों पर गिर देता है बम

कहा-जिनकी सेना 4 लाख महिलाओं से दुष्कर्म करे, उन्हें दूसरों को सिखाने का हक नहीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर झूठे प्रचार करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। ओपन डिबेट के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है और नरसंहार करता है।

हरीश ने कहा, जो अपने लोगों पर बम गिराए और 4 लाख महिलाओं के साथ रेप जैसा अमानवीय अपराध करे, उसे दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ और बढ़ा-चढ़ाकर बातें करता है। हरीश ने यह बयान उस समय दिया, जब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने आरोप लगाया कि कश्मीरी महिलाएं दशकों से यौन हिंसा झेल रही हैं। वहीं, भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।

बरेली में अब तगड़ा फंस गया मौलाना तौकीर रजा!

इधर बुलडोजर ऐक्शन, उधर योगी की पुलिस ने मांग ली 6 साल पुराने केस में रिमांड

बरेली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद कार्रवाइयों का दौर जारी है। जिले में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल हो गया था। इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा खां समेत कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से मौलाना तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा पर साल 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान बरेली में हुए उपद्रव के मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, उसे लगता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि

न जाम होगा और न ही कर्फ्यू लगेगा लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल है। उनके और उनके करीबियों को जेल भेजने के साथ ही अवैध निर्माण पर बुल्डोजर भी गरज रहा है।

फिजिक्स का नोबेल 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को

● बिजली सर्किट में क्वांटम टनलिंग के लिए मिला

स्कॉटहोम (एजेंसी)। इस साल फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को मिला है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है।

आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी-कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस टनलिंग को बिजली के सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में देखा है, जो पहले असंभव माना जाता था।

यूपी में भीड़तंत्र को सत्ता का मिल रहा है संरक्षण

● राहुल गांधी बोले-रायबरेली में इंसान नहीं, संविधान की हुई है हत्या

दलित युवक की पीटकर हत्या, मार खाते हुए राहुल का नाम लिया था

रायबरेली (एजेंसी)। रायबरेली में मॉब लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा- दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। राहुल ने मंगलवार को एक्स पर लिखा- संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, इंसाफ की जगह डर ने। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है।

मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल, 2 अक्टूबर को हरिओम पासवान की हत्या हुई थी। शुरू में कहा गया था कि युवक ड्रोन चोर था। उसी दिन युवक को पीटने और उसकी लाश के वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और वीडियो सामने आया, जिसमें मार खाते हुए युवक राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है, यहां सब 'बाबा' वाले हैं। इस मामले में ऊंचाहार संजय कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।

एअर इंडिया की कोलंबो-चेन्नई फ्लाइट के इंजन से टकराया पक्षी

चेन्नई (एजेंसी)। एअर इंडिया की कोलंबो-चेन्नई फ्लाइट के इंजन से मंगलवार को एक पक्षी टकराने (बर्ड हिट) से फ्लाइट को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइन ने चेन्नई से कोलंबो जाने वाली वापसी उड़ान को फिलहाल रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान जब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तभी उसके इंजन से पक्षी टकरा गया, जिससे विमान के इंजन से आवाज आने लगी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतार लिया। घटना के समय फ्लाइट में 158 पैसेंजर्स सवार थे। सभी पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बिहार की सभी सीटों पर गौ भक्त लड़ेंगे चुनाव

● बिहार में 'गौ मतदाता संकल्प यात्रा' की शुरुआत

अविमुक्तेश्वरानंद बोले-मजबूरी में आगे आना पड़ा

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)। मुजफ्फरपुर में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारने का इलाके किया है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। जिसका उद्देश्य है सनातन धर्म, गौ माता की रक्षा और समाज में सांस्कृतिक जागरुकता का प्रसार। एक सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है, जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। जिस दिन गौ माता सुरक्षित होंगी, उसी दिन भारत की आत्मा भी सुरक्षित होगी।

कादरी को पार्षद पद से हटाने की तैयारी

पहली बार किसी पार्षद को बर्खास्त करने की कार्रवाई निगम में होगी

इंदौर। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के मामले में आरोपी पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाने का प्रस्ताव भाजपा की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया। भाजपा पार्षद दल की बैठक में पिछली महापौर परिषद की बैठक में यह तय हुआ था कि तमाम पार्षदों की मौजूदगी में प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में यह तय हो गया है कि नगर निगम से पार्षद कादरी की रवानगी हो जाएगी।

बैठक में इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि पार्षद दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई थी। सभी पार्षदों को व्हिप जारी किया गया है कि निगम सम्मेलन के दिन सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। इंदौर के इतिहास में पहली बार किसी पार्षद को बर्खास्त करने की कार्रवाई

सम्मेलन के लिए भाजपा पार्षदों को व्हिप जारी

नगर निगम के सम्मेलन में होने जा रही है। पार्टी ने सभी पार्षदों को स्पष्ट निर्देश कि उस दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। यह देश की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है। मिश्रा ने आगे कहा कि लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले और आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधी को निगम परिषद में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

महापौर ने कमिश्नर को पत्र लिखा

आरोपी अनवर कादरी इंदौर के वार्ड नंबर 58 से कांग्रेस के पार्षद हैं। उनकी पार्षदी समाप्त करने की प्रक्रिया को जून माह से ही अमल में लाया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 20 जून को तत्कालीन कमिश्नर दीपक सिंह को इस बारे में पत्र लिखा था। उन्होंने कादरी को पद से हटाने का अनुरोध किया था। महापौर ने अपने पत्र में बताया था कि अनवर कादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें पद से हटाना जरूरी है।

गंभीर आरोप जो लगाए गए

पार्षद अनवर कादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जून माह का है, जब एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दो युवकों ने हैरान करने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि कादरी ने उन्हें पैसे दिए, ताकि वे हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन और वेश्यावृत्ति की ओर धकेलें। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया था और पुलिस ने फौरन मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद अनवर कादरी फरार हो गया, जिसे पुलिस भी नहीं ढूंढ सकी। बाद में आरोपी ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

राजवाड़ा में ई-रिक्शा, ऑटो पर रोक व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात

यातायात सुधार के लिए अतिरिक्त पुलिस बल सक्रिय रहेगा

इंदौर। दीपावली और करवा चौथ के पूर्व राजवाड़ा एवं आसपास के बाजारों में लगने वाले जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने मंगलवार से राजवाड़ा क्षेत्र में ई-रिक्शा और ऑटो के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही,यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

मंगलवार देर शाम अधिकारियों ने राजवाड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया और व्यापारियों के साथ-साथ तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों से फीडबैक लिया। निरीक्षण में पाया गया कि जाम का मुख्य कारण कृष्णपुरा छत्री और राजवाड़ा पहुंचने वाले मुख्य मार्गों पर खड़ी ऑटो और ई-रिक्शा हैं, जो सवारियों को बीच सड़क पर रोककर यातायात बाधित कर रही थीं। यातायात अधिकारी द्वारा बताया कि दीपावली और करवा चौथ के चलते हर दिन क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से

राजवाड़ा,पीपली बाजार,जवाहर मार्ग, सीतला माता बाजार, मारोठिया और आसपास के इलाकों में ई-रिक्शा और ऑटो प्रवेश नहीं करेंगे। यातायात सुधार के लिए अतिरिक्त पुलिस बल पूरे दिन सक्रिय रहेगा और भीड़ नियंत्रण,गाड़ी पार्किंग तथा सड़कों पर अव्यवस्था रोकने के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरवासियों और खरीदारी करने आए लोगों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

7 साल के बेटे को बचाने गई मां को पीटा

इंदौर। हीरानगर में एक 7 साल के बच्चे और एक गर्भवती महिला से मारपीट का मामला सामने आया। जब आरोपी बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था। तब महिला बचाने आई। उसने महिला को भी पीट दिया। उसके पेट में भी लात मार दी। कबीटखेड़ी निवासी महिला रजनी वर्मा की शिकायत पर एक लड़के कुणाल के खिलाफ मारपीट की धाराओं में हीरानगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि वह गृहिणी है। कुछ दिन पहले अपनी मां के पास रहने आई है। घर के पास रविवार शाम कुणाल नाम का लड़का उनके 7 साल के बेटे से मारपीट कर रहा था। जब रजनी वहां पहुंची तो आरोपी कुनाल ने उसके साथ मारपीट कर दी। रजनी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके पेट पर लात मार दी। जिसमें वह सड़क पर गिर गई। इसके बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता की बहन सविता भी वहां पहुंची। कुणाल ने उनके साथ भी मारपीट की कुनाल इसके बाद मौके पर बहनों को धमकी देकर भाग गया। पीड़िता को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इधर मामले में आरोपी पर एफआईआर की है।

ब्रोकर और डॉक्टर पर बार में हमला

इंदौर। गुमास्ता नगर रिंग रोड स्थित तंदूरी बार में जेल से छूटे बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर और डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर कार्तिक उर्फ टोनू शिंदे अपने दोस्त डॉ भरत सोनी के साथ बार में शराब पीने पहुंचे थे। इसी दौरान पास की टेबल पर बैठे मोहित और उसके साथियों से घूरने की बात पर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मोहित ने कार्तिक के चेहरे पर बीयर की बोतल से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। जब डॉक्टर ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया और मौके से सामान फेंकते हुए भाग निकले। घटना की सूचना रविवार रात में पुलिस को दी गई। कार्तिक को प्राथमिक इलाज के लिए डॉक्टर अपने निजी अस्पताल लेकर गए। घटना स्थल द्वारकापुरी और चंदन नगर थाने की सीमा में आता है, जहां नियमित रूप से पुलिस चेकिंग होती है।

पुलिस की सतर्कता से वारदात टली

इंदौर। परदेशीपुरा पुलिस की सक्रियता और तेज कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई। एमआर-4 रोड स्थित साईं मंदिर के पास डकैती की योजना बना रहे चार शातिर बदमाशों को पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ लिया। ये बदमाश सुनसान इलाके में लूटपाट की तैयारी में थे और पुलिस टीम को देखकर नाले में कूदकर भागने की कोशिश की। लेकिन, पुलिस ने पीछा करके सभी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। टीआई आरडी कानवा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और दो चाकू भी बरामद किए गए। सभी आरोपी पहले से करीब दो दर्जन अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने आदर्श पिता अशोक उर्फ मुन्ना तिवारी निवासी फिरोज गांधी नगर, राज पिता ओमप्रकाश वर्मा निवासी शीलनाथ कैंप, राकेश पिता बैजनाथ रायकवार निवासी नई जीवन की फेल तथा नागेश पिता देवीदास वाघ निवासी शिवाजी नगर को पकड़ा है। पुलिस कार्रवाई के बीच बदमाशों का साथी आशीष पाल मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीमें गठित की गई है।

पत्थर मारकर युवक को घायल किया

इंदौर। खजराना इलाके में निकाह में गए युवक का विवाद के चलते आरोपियों ने पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया। घटना एचबीके गार्डन खजराना की है। फरियादी जकी मुल्तानी पिता जुबेर मुल्तानी निवासी माणिक बाग की शिकायत पर आरोपी दानिश, अफसान और जैद निवासी ग्रीन पार्क कालोनी पर केस दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ निकाह के कार्यक्रम में आया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं और मेरा बुआ का बेटा मुल्तानी गार्डन से बाहर निकले, तभी अफशान मुल्तानी गालियां देने लगा। जब गाली देने से मना किया तो दानिश और अफसान ने मारपीट की तथा जैद ने पास में पड़े पत्थर उठाकर मार दिया।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश

किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई अंतर्विभागीय समन्वय समिति एवं समय-सीमा पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक में विभागों की कार्यप्रणाली का बारीकी से परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने राजस्व सहित महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, गृह, सहकारिता, लोक निर्माण, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभागों के लंबित प्रकरणों को तय समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आमजन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने सोयाबीन खरीद भावांतर भुगतान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से तुरंत कराया जाए और मंडियों में बैठने की व्यवस्था,पानी,पार्किंग, सीसीटीवी,पीओएस मशीन तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर स्टॉक की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर वर्मा ने सख्त रुख अपनाया।

एलायंस एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से दिल्ली उड़ान 3 दिन सीमित की

बुकिंग बंद की जो जल्द फिर शुरू होगी, 28 अक्टूबर से चलेगी

इंदौर। एलायंस एयर इंदौर से अपनी उड़ानों को सीमित करेगी। 28 अक्टूबर से इंदौर से दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ान रोज के बजाए सप्ताह में 3 दिन ही चलेगी। 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल में अपनी उड़ानों की बुकिंग बंद करने के साथ ही इन्हें वेबसाइट से हटा दिया गया है।

सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा को सौंपने के बाद सरकार के पास अब सिर्फ एलायंस एयर ही बची है। एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद ही एलाइंस एयर ने इंदौर से दिल्ली के लिए उड़ान की शुरुआत की थी। ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया ने बताया कि अभी कंपनी रोजाना दिल्ली जाने और आने वाली एक-एक उड़ान का संचालन करती है। यह फ्लाइट (9आई-627/628) शाम 5.30 बजे दिल्ली से रवाना होकर 7.40 बजे इंदौर आती है और इंदौर से रात 8.05 बजे रवाना होकर 10.10 बजे दिल्ली पहुंचती है।

लेकिन कंपनी ने 26 अक्टूबर से इन दोनों ही उड़ानों की बुकिंग बंद कर दी है। इसे लेकर यह संभावना भी जताई जा रही थी कि कंपनी इंदौर से अपनी उड़ानों को बंद कर सकती है। इस मामले में कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 28 अक्टूबर से इस उड़ान को नियमित के बजाए सप्ताह में तीन दिन मंगल, गुरु और शनिवार को ही संचालित किया जाएगा। कंपनी जल्द ही इसकी बुकिंग भी शुरू करेगी। फ्लाइट के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे दोबारा नियमित भी किया जा सकता है।

उड़ानें 16 तक निरस्त

कंपनी ने इस उड़ान को 16 अक्टूबर तक के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी की ओर से इसके लिए ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया है। साथ ही जिन यात्रियों ने इन उड़ानों में बुकिंग की थी उन्हें रिफंड और री बुकिंग का विकल्प दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अक्सर उड़ानें लेट हो रही हैं और इंदौर में एयरपोर्ट को रात 10.30 बजे बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उड़ानों को निरस्त किया जा रहा है।

सानंद के मंच पर 'सुंदर मी होणार' का मंचन लगातार तीन दिन तक

इस नाटक के पहले मंचन में पुल देशपांडे ने काम किया

इंदौर। सानंद न्यास के पांच दर्शक समूहों के लिए पुल देशपांडे के नाटक 'सुंदर मी होणार' का मंचन 10, 11 और 12 अक्टूबर को स्थानीय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह खंडवा रोड इंदौर में होगा। पहली बार इस नाटक का प्रयोग 30 अप्रैल 1958 को हुआ था, जिसमें खुद पुल देशपांडे ने अभिनय किया था।

टीवी कलाकारों द्वारा अभिनीत इस नाटक के कलाकार हैं अभिजीत चव्हाण, स्वानंदी टिकेकर, अमोल बावडेकर, श्रुति पाटिल, सर्जन देशपांडे, विराजस ओढेकर, आस्ताद काळे, श्रुजा प्रभुदेसाई। इस नाटक के लेखक पुल देशपांडे, निर्देशक राजेश देशपांडे, नेपथ्य संदेश बेंद्रे संगीत मिलिंद जोशी, प्रकाश योजना, अथर्व गोखले, वेशभूषा मंगल केंकरे, सूत्रधार नितिन नाईक और निर्माता आकाश भडसावळे, करण देसाई।

सानंद न्यास के अध्यक्ष जयंत भिसे एवं मानव सचिव संजीव वावीकर ने बताया कि इस नाटक का प्रथम प्रयोग 30 अप्रैल 1958 को हुआ जिसमें स्वयं पुल देशपांडे व सुनीता बाई साथ में दाजी

भटावडेकर, विजय जयवंत, आत्माराम भिड़े, काशीनाथ घाणेकर जैसे नामी कलाकारों ने काम किया। बाद में डॉ श्रीराम लागू, वंदना गुप्ते, डॉ गिरीश ओक, रवि पटवर्धन, कविता लाड जैसे कलाकारों ने विजय केंकरे के दिग्दर्शन में नाटक का मंचन किया। आकाश कारण ने इस कलात्मक नाटक को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह रहे हैं।

सानंद न्यास के भिसे एवं वावीकर ने बताया कि 3 दिन एवं 5 प्रयोगों में होने वाले नाटक सुंदर मी होणार का मंचन 10 अक्टूबर शुक्रवार को मामा मुजुमदार समूह के लिए सायं. 6.30 बजे, 11 अक्टूबर शनिवार को रामुभैय्या दाते समूह के लिए अपराह्न 4 बजे, सायं 7.45 बजे राहुल बारपुते समूह के लिए, इसी प्रकार 13 अक्टूबर, रविवार को वसंत समूह के लिये अपराह्न 4 बजे एवं सायं 7.45 बजे बहार समूह के लिए होगा।

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए

इंदौर। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और दिवाली व छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान बढ़ी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों उधना-बलिया स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल एवं गांधीधाम-सियालदह स्पेशल, के संचालन अवधि को पुनः विस्तारित किया है। उधना-बलिया स्पेशल गाड़ी (संख्या 09041) का अंतिम फेरा 9 अक्टूबर को है, पर अब यह 27 नवंबर तक उधना से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 09042 बलिया-उधना स्पेशल का अंतिम फेरा 10 अक्टूबर निर्धारित है, 28 नवंबर तक बलिया से प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल गाड़ी (संख्या 09061) का अंतिम फेरा 6 अक्टूबर का था, अब यह 24 नवंबर तक बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। वहीं गाड़ी (संख्या 09062) बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल का अंतिम फेरा 9 अक्टूबर तक तय है, पर अब यह 27 नवंबर तक बरौनी से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। गांधीधाम-सियालदह स्पेशल गाड़ी (संख्या 09437) का अंतिम फेरा 8 अक्टूबर को निर्धारित है। लेकिन, इसे अब 26 नवंबर तक गांधीधाम से प्रत्येक बुधवार को चलाया जाएगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल का अंतिम फेरा 11 अक्टूबर को है, यह अब 29 नवंबर तक सियालदह से प्रत्येक शनिवार को चलेगी।

जीएनटी मार्केट में देर रात शुरू होती है अवैध लकड़ी की मंडी

फर्जी टीपी और सांठगांठ से बढ़ रहा अवैध कारोबार

इंदौर। शहर की जीएनटी मार्केट (लकड़ी मंडी) में एक बार फिर अवैध लकड़ी के व्यापार ने जोर पकड़ लिया। रात के अंधेरे में वन माफियाओं द्वारा जंगलों से काटी गई लकड़ी को खुलेआम लकड़ी मंडी में दलालों द्वारा नीलाम किया जा रहां है। यह पूरा रैकेट वन माफियाओं और वन विभाग के तीन अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार देवास, धार, धामनोद, मनावर,सरदारपुर, शाजापुर,कुक्षी,बाग, टांडा, गुना, अशोकनगर, राघोगढ़, बालाघाट, सिवनी, उज्जैन, देवास और जबलपुर के जंगलों से हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। लकड़ी को फर्जी टीपी (अनुज्ञा पत्र) के सहारे इंदौर तक लाया जा रहा है। यहां जीएनटी मार्केट में दलाल इन लकड़ियों को खुलेआम बेच रहे हैं, जबकि विभागीय अधिकारी अनदेखी का रुख अपनाए हैं। लकड़ी मंडी से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया कि यह गोरखधंधा वन विभाग के तीन अधिकारियों की मदद से संचालित है। मंडी में आने वाली लकड़ियों पर अनिवार्य 'हैमर मार्किंग' तक नहीं होती,जिससे स्पष्ट है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे इसे वैध बताया जा रहा है।

बीते चार दिनों से मंडी में लकड़ी की अवैध

आमद तेजी से बढ़ी है। हर दिन 10 से 15 ट्रक ट्राले,आईसर,अशोक लीलैंड, छोटा हाथी एवं अन्य प्रकार के जंगलों से कटाई की लकड़ी लेकर इंदौर पहुंच रहे हैं। चार दिनों से सुमित वासु डायमंड छोटू, राजू वासु और शर्मा नामक दलालों की गाड़ियां मंडी में लाई, लेकिन विभाग की मिलीभगत के कारण किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले पर डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं थी, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वन माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

लकड़ी मंडी में यह गोरखधंधा रात 10 बजे के बाद शुरू होता है। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक अन्य वाहन भर भरकर लकड़ी मंडी में लाई जाती है और सुबह तक उसका सौदा निपटा दिया जाता है। विभागीय अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता इस पूरे प्रकरण पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर यह कारोबार किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है। लकड़ी मंडी के कई दलाल इस अवैध कारोबार में सक्रिय हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पूर्व में वन रक्षक से मारपीट और फर्जी टीपी कांड में आरोपी रह चुके हैं। बावजूद इसके, विभाग ने उन्हें कार्रवाई से बचा लिया था। इन दलालों में डायमंड, छोटू शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सुमित वासु और राजू वासु (सेठ) के नाम सामने आए हैं।

एडीएम रोशन राय को आपदा प्रबंधन सहित 36 शाखाओं का प्रभार सौंपा

प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त करने के लिए नए सिरे से कार्य विभाजन

इंदौर। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने चार अपर कलेक्टरों के कार्यों को विभाजित किया है। साथ ही जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच नया कार्य-विभाजन भी लागू हो गया। सोमवार को जारी आदेश से पूर्व का समस्त कार्य विभाजन निरस्त कर दिया गया। अब चारों अपर कलेक्टरों को न्यायालयीन कार्यों से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक की स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई। जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार (आईएएस) को मल्हारगंज, हातोद और देपालपुर अनुभागों के राजस्व और न्यायालयीन प्रकरणों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, धार्मिक न्यास एवं वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रकरणों का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया है। वे लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रथम अपील प्राधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा एवं पीडीएस व्यवस्था के प्रभारी भी रहेंगे।

रोशन राय को 36 शाखाएं- अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और अपर कलेक्टर रोशन राय को राऊ, सांवेर एवं खुड़ैल अनुभागों के साथ विवाह अधिनियम, पासपोर्ट एवं नागरिकता जांच, प्रेस रजिस्ट्रेशन, विभागीय जांच शाखा, हेल्पलाइन शाखा और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील दायित्व सौंपे गए हैं। लोकसभा एवं विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाना भी उनकी ही जिम्मेदारी होगी।

रिंकेश वैश्य को नई जिम्मेदारी- अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य को कनाड़िया, महू, जूनी इंदौर और मिचौली हप्सी अनुभागों के न्यायालयीन कार्यों के अतिरिक्त नजूल, लेखा, परिवहन (आरटीओ), राहत शाखा, रेडक्रॉस सोसायटी एवं कॉलोनी सेल जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई।

नई नीति के तहत इंदौर जिले में 585 नए मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव

मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या घटाने से बदलाव आया

इंदौर। जिला निर्वाचन कार्यालय ने लगभग 28.65 लाख मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिले में 585 नए मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की हाल ही में लागू की गई नीति के तहत आया है, जिसमें प्रति मतदान केंद्र अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है।

इस बदलाव के कारण जिले के मतदान ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता पड़ी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतिम दुबे ने बताया कि फ़िलहाल जिले में 2,625 मतदान केंद्र हैं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो इंदौर जिले में कुल 3,210 मतदान केंद्र होंगे। दुबे ने बताया कि पहले एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता होने की सीमा थी, जिसे अब घटाकर 1200 मतदाताओं तक सीमित कर दिया गया। यही इस बड़े प्रस्ताव का मुख्य कारण है।मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने से बूथ लेवल अधिकारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि, प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बीएलओ नियुक्त किया जाता है। इसके लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

दुबे ने कहा कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करने से निर्वाचन कार्यों के लिए प्रशिक्षित और भरोसेमंद कर्मचारी बल उपलब्ध होता है। यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कार्यालय को भेजा जा चुका है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। यह कदम निर्वाचन कार्यालय की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्रों में भीड़ कम करना, प्रतीक्षा समय घटाना और तेजी से बढ़ते जिले के हर मतदाता के लिए सुगम मतदान अनुभव सुनिश्चित करना शामिल है।

संपादकीय

सीजेआई पर हमला अस्वीकार्य है

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस बी.आर. गवई पर कोर्ट के ही एक वरिष्ठ वकील द्वारा जूता फेंककर हमला करने की कोशिश की सर्वथा निंदनीय और अस्वीकार्य है। बताया जाता है कि हमलावर वकील जस्टिस गवई द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों से नाराज था। लेकिन जो हरकत उसने की है, उससे न केवल जस्टिस बल्कि समूची न्यायपालिका की छवि पर बट्टा लगा है। हालांकि इस अशोभनीय कृत्य के बाद जस्टिस गवई ने आरोपी को माफ कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है, वो ठीक भी है। ऐसी हरकतों को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य न्यायाधिपति से बात की और उनके धैर्य की प्रशंसा की। पीएम ने इसे अत्यंत निंदनीय कृत्य बताकर उसकी भर्त्सना की। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक घटना उस समय हुई जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ मामलों की सुनवाई कर रही थी। हमलावर वकील मंच के पास गया और अपना जूता निकालकर न्यायाधीश पर फेंकने का प्रयास किया। आरोपी वकील राकेश किशोर पहले अपना जूता फेंका और हाथ उठाकर बताया कि जूता उसने फेंका है। लेकिन जूता चीफ़ जस्टिस और जस्टिस चंद्रन के पीछे जाकर गिरा। तब हमलावर ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस को निशाना बनाया था। बाद उसको कोर्ट रूम सिक्योरिटी ने डीटेन कर लिया। इस अप्रत्याशित घटना के उपरांत चीफ़ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि वो इस घटना से विचलित हुए बिना बहस जारी रखें। एक अखबार के अनुसार आरोपी वकील ने कोर्ट नंबर 1 में कार्यवाही के दौरान सुबह करीब 11:35 बजे अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और सीजेआई गवई पर फेंक दिए। लेकिन उन दो मिनटों में जो हुआ, उसने सभी को भौंचक्का कर दिया, क्योंकि कोर्ट और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अपना डेकोरम और शिष्टाचार होता है। बेशक कोर्ट में वादी प्रतिवादी मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन वह कानूनी लड़ाई होती हैं। वहां इस तरह मारपीट और वो भी जज के खिलाफ बिल्कुल असामान्य बात है। हमले के बाद बाहर निकालने के दौरान वो वकील चिल्लाता रहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस घटना के बाद एक बयान में आरोपी ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। उसने जो किया, वह दैवी शक्ति ने उससे कराया। उधर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीओएआरए) और कांग्रेस पार्टी ने हमले की निंदा की है। हमलावर वकील राकेश किशोर को बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने तत्काल निलंबित कर दिया है। यह जानकारी भी सामने आई है कि हमलावर वकील 2011 से सुप्रीम कोर्ट बार का है। उसने पिछले दिनों सीजेआई की ओर से भगवान विष्णु पर किए गए कमेंट से आहत होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यह भी सही है कि खजुराहो के जिस मंदिर में विष्णु की खंडित मूर्ति को नवीनीकृत लगाने सम्बंधी जिस याचिका पर सीजेआई ने जो टिप्पणी की थी, वह भी अनावश्यक थी। वह यहकर भी याचिका खारिज कर सकते थे कि यह मामला एएसआई से सम्बंधित अदालत इस मामले में दखल नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु और सनातन धर्म को लेकर बेवजह टिप्पणियां कीं, जिससे देश में गलत संदेश गया। हालांकि बाद में सीजेआई ने उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन लगता है कि आरोपी वकील के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर की मूर्ति की वजह से न्याय के मंदिर को जूता फेंककर अपवित्र किया जाए।

नजरिया

डॉ.संजीव कुमार

लेखक सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।

दलित राजनीति और सत्ता का षड्यंत्र

इंदिरा हटाओ के नारे के पीछे जनता पार्टी की यही मनसा थी (जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का स्वप्न दिखाकर) परंतु जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक बार फिर जगजीवन राम (दलित) को पीछे कर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर संतुष्ट कर दिया गया। जिससे पार्टी में असंतोष बना रहा। यह बात जय प्रकाश और मोरार जी को खटक रही थी ऐसे में 1978 में भारत का पहला सेक्स स्कैण्डल सामने आया। 20 अगस्त 1978 को दिल्ली के मोहन नगर में एक कार दुर्घटना हुई। सुरेश राम (जगजीवन राम के बेटे) अपनी मर्सिडीज बेंज कार चला रहे थे, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी (21 वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा, मेरठ के एक जाट परिवार से) भी सवार थी। कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घबरा गए सुरेश ने कार मोहन मीकिन्स फैक्ट्री के कैंपस में छोड़ दी और सुषमा के साथ पैदल भाग निकले।

देश के आठ दशक की राजनीति में दलित मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बन चुके हैं पर प्रधानमंत्री की दावेदारी में वह अभी भी बहुत पीछे खड़े हैं। आपातकाल के बाद एक बार अवश्य अवसर बना किसी दलित के प्रधानमंत्री बनने का पर एक बहुत बड़े साजिश से वह पूरा होते-होते रह गया। आज राजनीति में कोई 15-20 साल विधायक और सांसद बन जाता है तो उसे कद्दावर नेता माना जाता है। पर आज भी भारतीय लोकतंत्र में जिस नेता के पास सबसे ज्यादा समय तक सदन का सदस्य होने का रिकॉर्ड हैं वह है भारतीय राजनीति के 'बाबू जी' बाबू जगजीवन राम। वह भारतीय सदन में लगभग 50 साल तक लगातार सदन के सदस्य बने रहे हैं। ऐसा तिलिस्म आज भी किसी के पास हासिल नहीं है जो उनके रिकॉर्ड तक पहुंच सके। ऐसे में जाहिर है जो व्यक्ति गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक रह चुका हो वह प्रधानमंत्री का सपना जरुर देखेगा। और वह स्वप्न भी लगभग पूरा ही हो चूका था लेकिन एक विशाल राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से वह कभी पूरा न हो सका।

आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण की जनता दल की गुटबंदी के प्रमुख नेता थे जगजीवन राम। कांग्रेस में उन्हें वह सब कुछ मिला जिसके वह हकदार थे। कांग्रेस ने उनके कंधे पर खड़े होकर दशकों दलित राजनीति की, ऐसे में जगजीवन राम और राज नारायण को भी लगा की क्यों न जगजीवन राम भी एक बार प्रधानमंत्री बने। चुनावों के दौरान जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जगजीवन राम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस से उनके इस्तीफे को 'जे-बम' कहा गया जिसने कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया था।

इंदिरा हटाओ के नारे के पीछे जनता पार्टी की यही मनसा थी (जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का स्वप्न दिखाकर) परंतु जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक बार फिर जगजीवन राम (दलित) को पीछे कर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर संतुष्ट कर दिया गया। जिससे पार्टी में असंतोष बना रहा। यह बात जय प्रकाश और मोरार जी को खटक रही थी ऐसे में 1978 में भारत का पहला सेक्स स्कैण्डल सामने आया। 20 अगस्त 1978 को दिल्ली के मोहन नगर में एक कार दुर्घटना हुई। सुरेश राम (जगजीवन राम के बेटे) अपनी मर्सिडीज बेंज कार चला रहे थे, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी (21 वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा, मेरठ के एक जाट परिवार से) भी सवार थी। कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घबरा गए सुरेश ने कार मोहन मीकिन्स फैक्ट्री के कैंपस में छोड़ दी और सुषमा के साथ पैदल भाग निकले। फैक्ट्री मैनेजर अनिल बाली ने उन्हें पहचान लिया उन्हें और सुरक्षित जगह पर छिपा दिया।

कहा जाता है सुरेश की कार का पीछा जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता, केसी त्यागी (राज नारायण के करीबी) और ओमपाल सिंह (चौधरी चरण सिंह के करीबी), कर रहे थे। उन्होंने कार की तलाशी ली तो अंदर 40-50 अश्लील तस्वीरें मिलीं जिनमें सुरेश और सुषमा की अंतरंग तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें कथित रूप से सुरेश के सहयोगी एपी सिंह ने ली थीं। बाद में ये तस्वीरें बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनीं। इन्हें सूर्या पत्रिका,नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित करवा कर जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के स्वप्न को ही जड़ से समाप्त कर दिया गया। आज जब देश में शिथिल हो चुकी दलित राजनीति थोड़ी चौकन्नी हुई है तो फिर एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है।

वर्तमान में जो आरोप प्रत्यारोप चर्चा में है वह है इस वक्त देश के सबसे चर्चित लोकप्रिय दलित नेता चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का विवाद। पिछले कई महीनो से रोहिणी नगीना सांसद चंद्रशेखर पर कई संगीन आरोप लगा रही है। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाएं, उन्हें देश का बड़ा दलित नेता बनाने की लालच दी और कई बड़े सपने दिखाए। वह अपने और चंद्रशेखर के संबंध पर कह रही हैं कि उन्हें पता नहीं था कि चंद्रशेखर शादीशुदा व्यक्ति है। रोहिणी एक पढ़ी-लिखी कुशल और समाजसेविका है। उन्हें 2019 में एक करोड़ का प्रवासी भारतीय छात्रवृत्ति भी प्रदान हो चुका है। इस राशि से उन्होंने स्विट्जरलैंड से बिजनेस मैनेजमेंट से पीएचडी की और अब वही अपना सामाजिक कार्य कर रही हैं। मार्च 2023 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ में भाषण देकर देश भर में सुर्खियां प्राप्त की थी। मजेदार बात यह है कि एक दलित होने के बावजूद अपने भाषण की शुरुआत इन्होंने जय श्री राम कहते हुए की थी (आम तौर पर दलित वैचारिकी रखने वाले ऐसे नारों से बचते है)। वे लगातार चंद्रशेखर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप पर आरोप लगाती जा रही है।

अब सोचने वाली बात यह है कि जो चंद्रशेखर जिस पार्टी के विचारधारा से लड़ते - लड़ते सोलह माह जेल तक काट चुका है, जिसे समाज हित में लड़ने के लिए गोलियां तक मारी जा चुकी है वह भला किसी पार्टी का दलाल कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपने और अपने विचारों के दम पर आज संसद में पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं उठा रहा है, जिसे आज भारतीय राजनीति में एक कद्दावर नेता माना जा रहा है, जिसके दहाड़ से बड़ी-बड़ी पार्टियां अपनी रणनीतियां बदलने लगी है उसे भला कोई पार्टी क्या दे सकती है? और अब रही बात घावरी के आरोप की तो यह बात एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि जो व्यक्ति आधी रात को किसी महिला पर हमले के लिए पूरे देश से लड़ जाता है, वह इतना घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता।

दरअसल घावरी भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है जो लगातार इस देश में दलित राजनीति को कमजोर करने का प्रयास करता रहा है। भारत का एक तबका जो दलितों को कभी भी अपने सामने कुर्सी पर बैठते हुए देखना पसंद नहीं करता, उसके सामने जब भी कभी ऐसी चुनौती आती है जिससे उसे अपने सत्ता के जाने का डर लगता है वे वैसे ही उस डर को समाप्त करने के लिए गहरी साजिश रचना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रही चुकी दलित समाज की प्रिय नेता मायावती को भी अनेकों ऐसे मुकदमे झेलने पड़े हैं जिसमें ताज कॉरिडोर, स्मारक और संग्रहालय का निर्माण इत्यादि शामिल है। इन मुकदमों में उन्हें उलझा कर उनकी राजनीति को कमजोर करने का प्रयास किया गया जिसमें कि विपक्षी लोग काफी हद तक सफल भी हुए हैं। सत्ता में बैठे सामन्ती लोग दलित राजनीति को हमेशा छिन्नभिन्न देखना चाहते है, इसके लिए वे हर तरह का षड्यंत्र रचते रहते है फर्जी मुकदमों का मामला भी इसी का हिस्सा है।

2023 में वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाडी को भी एक ट्वीट के मामले में ऐसे ही फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी 2017 में चंद्रशेखर को एनएसए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है ,जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। 2019 में मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता बद्रीनारायण गोडको झूठे खनन के मुक़दमे में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति वर्ष देश भर में 10-15 प्रतिशत झूठे मुक़दमे दर्ज किए जाते है। अब देखना ये है की घावरी का दावा किस हद तक सही साबित होता है, क्योंकि आज देश भर में चंद्रशेखर की जो राजनीतिक छवि बनी है उसे हर प्रकार से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। घावरी का उन पर आरोप लगाना एक सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल ये है की आखिर यह सब कर कौन रहा है है ?और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है?

सामयिक

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जहरीली दवा बनी अभिशाप

इंसान की जीवन-रक्षा से जुड़ा दवा करोबार अपने देश में तेजी से मुनाफे की अमानवीय व अनैतिक हवस में बदलता जा रहा है। चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए महंगी और गैर जरुरी दवाएं लिखवाने का प्रचलन लाभ का धंधा हो गया है। इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने के नजरिये से कुछ समय पहले केन्द्र सरकार ने दवा कंपनियों से ही एक आचार संहिता लागू कर उसे कड़ाई से अमल में लाने की अपील की थी।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में सर्दी-खांसी की दवा के सेवन से 16 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सीरप स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया था, किंतु वह मौत का कारण बन गया। इसकी गुणवत्ता संदेह के दायरे में है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं दवा नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने कहा है कि संदिग्ध सिरप को परीक्षण के लिए 1 अक्टूबर को तमिलनाडु भेजा था। इसकी रिपोर्ट तीसरे दिन मिल गई थी। किंतु मप्र में 29 सितंबर से जांच जारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। जबकि इसी बीच स्वास्थ्य विभाग का कार्य देख रहे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सार्वजनिक बयान दे दिया कि सीरप के नौ नमूनों में हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं। यह सीरप श्रीसन कंपनी बनाती है, जिसकी उत्पादन इकाई तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। मप्र सरकार के कहने पर तमिलनाडु सरकार के औषधि प्रशासन विभाग ने कंपनी की उत्पादन इकाई से नमूने लेकर जांच की तो एसआर-13 बैच में हानिकारक रसायन डायथिलीन ग्लायकल (डीईजी) पाया गया। दवा में इसकी निर्धारित मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि इसका प्रतिशत जांच में 48 प्रतिशत से अधिक पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार सक्रिय हुई और इसके उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगा दी। मृतक बल-गोपालों का इलाज करने वाले छिंदवाड़ा के चिकित्सक डॉ प्रवीण सोनी पर मामला दर्ज करके,उन्हें फ़िलहाल जमानत पर रिहा कर दिया है। इन मौतों और इस रिपोर्ट के बाद सतर्कता बरतते हुए कई राज्य सरकारों ने इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी सलाह दी है कि दो वर्ष से छोटे बच्चों को कफ सीरप नहीं पिलाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया से लगता है कि प्रदेश में ही नहीं देश में निगरानी तंत्र कमजोर है।

यूपीए सरकार ने जब नकली दवाओं से छुटकारे के नजरिए से औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम बनाया था तब यह मान लिया गया था कि अब नकली दवाओं पर कमोबेश प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि इस कानून के तहत न केवल इस धंधे को गैर जमानती बना दिया गया था, बल्कि दवा बनाने वालों से लेकर बेचने वालों तक को दस साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया था। लेकिन देखने में आया है कि दवा दुकानों पर लगातार नकली दवाओं के भण्डार बरामद हो रहे हैं और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। साफ है, नकली दवा कारोबार न केवल बेखौफ जारी है बल्कि इसमें बेइंतहा इजाफा भी हो रहा है। यही नहीं ये दवाएं सरकारी अस्पतालों के माध्यम से भी धड़ल्ले से उपयोग में लाई जा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकारी चिकित्सा-तंत्र का एक बड़ा हिस्सा इस कारोबार को ताकत दे रहा है।

इसके पहले 2019-20 में जम्मू के रामनगर में भी एक फार्मा कंपनी के बनाए सीरप से 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। कंपनी पर एफआईआर हुई, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। वर्ष 2022 में हरियाणा की दवा कंपनी के सीरप से गांबिया में 70 और उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की मौतें हो गई थीं। सितंबर 2008 में भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी रैनबैक्सी की तीस जेनेरिक दवाओं को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। रैनबैक्सी की देवास (मध्य प्रदेश) और पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) में बनने वाली दवाओं के आयात पर अमेरिका ने रोक लगाई थी। अमेरिका की सरकारी संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) का दावा था कि रैनबैक्सी की भारतीय इकाइयों से जिन दवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका मानक स्तर अमेरिका में बनने वाली दवाओं से घटिया है। ये दवाएं अमेरिकी दवा आचार संहिता की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरी थीं। जबकि भारत की रैनबैक्सी ऐसी दवा कंपनी है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाओं का निर्यात करती है। रैनबैक्सी एक साल में कई हजार करोड़ की दवाएं देश व दुनिया में बेचती है। ऐसी ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी आचार संहिता के पालन के पक्ष में नहीं हैं। किसी बाध्यकारी कानून को अमल में लाने में भी ये रोड़ा अटकाने का काम करती हैं। क्योंकि ये अपना कारोबार विज्ञापनों व चिकित्सकों को मुनाफा देकर ही फैलाये हुए हैं।

छोटी दवा कंपनियों के संघ का तो यहां तक कहना है कि चिकित्सकों को उपहार देने की कुप्रथा पर कानूनी तौर से रोक लग जाए तो दवाओं की कीमतें 50 फीसदी तक कम हो जाएंगी। चूंकि दवा का निर्माण एक विशेष तकनीक के तहत किया जाता है और रोग व दवा विशेषज्ञ चिकित्सक ही पर्चे पर एक निश्चित दवा लेने को कहते हैं। दरअसल इस तथ्य की पृष्ठभूमि में यह मकसद अंतर्निहित है कि रोगी और उसके अभिभावक दवाओं में विलय रसायनों के असर व अनुपात से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वे दवा अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इस कारण चिकित्सक की लिखी दवा लेना जरूरी होती है।

इंसान की जीवन-रक्षा से जुड़ा दवा करोबार अपने देश में तेजी से मुनाफे की अमानवीय व अनैतिक हवस में बदलता जा रहा है। चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए मंहगी और गैर जरुरी दवाएं लिखवाने का प्रचलन लाभ का धंधा हो गया है। इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने के नजरिये से कुछ समय पहले केन्द्र सरकार ने दवा कंपनियों से ही एक आचार संहिता लागू कर उसे कड़ाई से अमल में लाने की अपील की थी। लेकिन संहिता का जो स्वरूप सामने लाया गया, वह राहत देने वाला नहीं था। संहिता में चिकित्सकों को उपहार व रिश्वत देकर न तो अनैतिक कारगुजारियों को लेकर कोई साफगोई है और न ही संहिता की प्रस्तावित शर्तें व कानून बाध्यकारी हैं। इन प्रस्तावों को लेकर दवा संघों में भी मतभेद हैं।

विज्ञान की प्रगति और उपलब्धियों के सरोकार आदमी और समाज के हितों में निहित हैं। लेकिन हमारे देश में मुक्त बाजार की उदारवादी व्यवस्था के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जब आगमन हुआ, तो उसके तईं जिस तेजी से व्यक्तिगत व व्यवसायजन्य अर्थ-लिप्सा और लूटतंत्र का विस्तार हुआ है, उसके शिकार चिकित्सक तो हुए ही, निगरानी तंत्र भी इसकी चपेट में है। नतीजतन देखते-देखते भारत के दवा बाजार में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की 70 प्रतिशत से भी ज्यादा की भागीदारी हो गई। इनमें से 25 फीसदी दवा कंपनियां ऐसी हैं जिन पर व्यवसायजन्य अनैतिकता अपनाने के कारण अमेरिका भारी आर्थिक दण्ड दे चुका है।

ऐसे हालात में चिकित्सक अनैतिकता और दवा कंपनियां केवल लाभ का दृष्टिकोण अपनाएंगी तो आर्थिक रूप से कमजोर तबका तो स्वास्थ्य चिकित्सा से बाहर होगा ही, जो मरीज दवा ले रहे हैं उनके मर्ज की दवा सटीक दी जा रही हैं अथवा नहीं इसकी गारंटी भी नहीं रह जाएगी? इस कारण सरकार ने 2009 के आरंभ में दवा कंपनियों के संघ से स्वयं एक आचार संहिता बनाकर अपनाने को कहा था। साथ ही सरकार ने यह हिदायत भी दी थी कि यदि कंपनियां इस अवैध गोरखधंधे पर अंकुश नहीं लगातीं तो सरकार को इस बाबत कड़ा कानून लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

लेकिन सरकारी चेतावनी की परवाह किए बिना दवा कंपनियों का संघ जो नई आचार संहिता सामने लाया, उसमें उपहार के रूप में लाभ देने का केवल तरीका बदला गया। मसलन तोहफों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। संहिता में केवल दवा निर्माताओं से उम्मीद जताई गई है कि वे चिकित्सकों को टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व नकद राशि नहीं देंगे। लेकिन वैज्ञानिक सम्मेलन, कार्यशालाओं और परिचर्चाओं के बहाने उपहार देने का सिलसिला और चिकित्सकों की विदेश यात्राएं जारी रहेंगी। जाहिर है आचार संहिता के बहाने चिकित्सक और उनके परिजनों को विदेश यात्रा की सुविधा को परंपरा बनाने का फरेब संहिता में जानबूझकर डाला गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि भारत में बनने वाली दवाएं करीब 35 प्रतिशत नकली होती हैं। एसोचेम के मुताबिक देश में 25 प्रतिशत की दर से हर साल इस कारोबार में इजाफा हो रहा है। बहरहाल भारत सरकार को दवाओं पर निगरानी के लिए मजबूत तंत्र खड़ा करने की जरूरत है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक हेमंत पाल
प्रबंध संपादक रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

अरुण अर्णव खरे

उनके चाहने वाले

चाहना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। मनुष्य योनि में जन्म लेते ही व्यक्ति माँ-बाप, भाई-बहिन, प्रकृति, मौसम, नदी, पहाड़ों, चाँद-तारों से लेकर खूबसूरत चेहरों, खूबसूरत नजारों और पता नहीं किस किस को चाहने लगता है। चाहना उसे सिखाना नहीं पड़ता। कुछ चीजों, लोगों और प्रकृति को चाहना उसे विरासत में मिलता है और कुछ को चाहना वह स्वयं सीख जाता है। कुछ को चाहकर उसे सुरक्षा मिलती है, अपनत्व मिलता है और कुछ को चाहकर आनंद की अनुभूति। इस हिसाब से देखें तो चाहने वाले केवल एक ही प्रकार के हो सकते हैं उनको अलग-अलग कैटेगरी में नहीं बाँटा जा सकता, लेकिन यहाँ हम जिन चाहने वालों की चर्चा करने जा रहे हैं उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है। वे केवल उनके चाहने वाले हैं। वे एकतरफा उन्हें ही चाहते हैं। इन चाहने वालों को कोल्हू के बैल अथवा ताँगे के घोड़े के समान केवल सीधा देखना आता है। इन्हें दाएँ-बाएँ देख कर दूसरी चीजों को चाहने की इजाजत नहीं है। इन्हें केवल उन्हें ही चाहना सिखाया गया है। इसके लिए इन्हें बकायदा प्रशिक्षित किया गया है।

चाहने वाले बड़े भावुक प्रकृति के होते हैं पर ये उनके चाहने वाले हैं, सबसे अलग और खास तरह से निर्मित। किसी बात पर भावुक हो जाना इनके मिजाज में नहीं है। भावुकता के तमाम कारकों को इनके मस्तिष्क से बड़े प्रयास से निष्क्रिय बनाया गया है। अब ये बलात्कार, लिंचिंग और बुलडोजर जैसी बातों पर भावुक नहीं होते, चुप्पी साधे रहते हैं और जो इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं उन्हें नीचा दिखाने और राष्ट्रद्रोही सिध्द करने में जुट जाते हैं। इन्हें भोर की पहली किरण के साथ ही हर दिन एक नया टास्क मिल जाता है और देर रात्रि तक ये करोड़ों लोगों के इनबॉक्स में जबर्दस्ती घुसपैठ कर उसे रोपित कर देते हैं। ये यह सब किसी को नीचा गिराने या ऊपर उठाने के लिए नहीं करते अपितु अपनी चाहत का प्रमाण देने के लिए करते हैं।

चाहने वाले बड़ी कोमल प्रवृत्ति के होते हैं पर ये उनके चाहने वाले हैं आम चाहने वालों से एकदम उलट। इनके दिल में कोमलता को पल्लवित करने वाले स्थान तक रक्त पहुँचाने वाली नलिका को अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे वह स्थान पूरी तरह से बंजर और कड़क हो गया है। इसी कारण से ये जेल से छूटे हत्या और बलात्कार के दोषियों का वीरोचित स्वागत कर पाते हैं, उनका प्रशस्तिवाचन कर पाते हैं।

चाहने वाले बड़े दिल के होते हैं। वे किसी की बुराई नहीं करते, दिल खोल कर सबकी प्रशंसा करते हैं। उनके चाहने वालों के पास भी दिल होता है, बड़ा तो नहीं ही होता है यह कई बार ये सिद्ध कर चुके हैं। इनका दिल किसी की प्रशंसा नहीं करता। इनका दिल केवल इन्हें जिंदा रखने का इकलौता काम करता है। चाहने वाले त्याग और समर्पण के पर्याय होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से उनके चाहने वाले भी इन गुणों से लबरेज हैं। ये चाहने वाले उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। प्रेम, सहिष्णुता, ममता, सद्भाव और विश्वास का त्याग, ये बहुत पहले कर चुके हैं। चाहने वाले निस्वार्थ होते हैं। उनके चाहने वाले भी निस्वार्थ हैं। सोशल मीडिया के अपने हर अकाउंट की डीपी में इन चाहने वालों ने अपनी फोटो के स्थान पर उनकी फोटो लगा रखी है।

आजकल उनके चाहने वाले परेशान हैं। चाहने वालों को आभास होने लगा है कि वे इस समय परेशान चल रहे हैं। चाहने वालों ने पिछले दिनों कई बार उनकी डायलॉग डिलीवरी में टाइमिंग को मिसमैच होते देखा है। चाहने वालों को पता है कि वे किस बात से परेशान हैं लेकिन चाहने वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें केवल चाहना ही आता है, उन्हें केवल चाहना ही सिखाया गया है और उन्हें केवल चाहते रहने के लिए विवश बनाया गया है। अपने चाहने वालों पर उनने निवेश भी भरपूर किया है। चाहने वालों को पता ही नहीं है कि कब उनके ब्रेन के नैसर्गिक साफ्टवेयर से ऐसी सारी कुकीज और सपोर्टिंग फाइल्स डिलिट की जा चुकी हैं जो चाहने के अलावा कोई दूसरा काम करने में सहायक हो सकती थीं। उनके चाहने वालों का कायाकल्प हो चुका है। अब वे इंसान नहीं रहे, वे एक डिजिटल, सुविधाजनक और स्वार्थ-नियंत्रित इकाई में बदल चुके हैं।

दृष्टिकोण

अरुण कुमार डनायक

लेखक गांधी विचारों के अध्येता हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारत और बदलती धारणाएं

मदर टेरेसा (1962) को गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार और बाद में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। पर भारत में एक वर्ग ने उन्हें 'धर्मांतरण एजेंडे' से जोड़कर कठोर आलोचना की। साहित्य में नोबेल विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर (1913) और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (1998) भी अपनी वैचारिक दृढ़ता के कारण तीखी आलोचनाओं से अछूते नहीं रहे। टैगोर पर यह आरोप लगाया गया कि 'जन गण मन' ब्रिटिश सम्राट की प्रशंसा में लिखा गया, जबकि विद्वानों ने इसे निराधार बताया। इसी तरह अमर्त्य सेन पर विश्वभारती की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के आरोप लगे, किंतु वे अब तक न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए और अधिकतर राजनीतिक विवाद ही माने गए।

बीसवीं सदी के सबसे बड़े नैतिक और राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं में से एक महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाँच बार नामांकित किया गया। गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा ने पूरे विश्व को दिशा दी, दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक उनके विचारों ने आंदोलनों को प्रेरणा दी, अनेक उपनिवेशों की आज़ादी का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया किंतु नोबेल समिति ने उन्हें योग्य नहीं माना। इसी तरह, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत , गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व शांति की राजनीति में अपनी गहरी भूमिका निभाई। किंतु उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मान्यता से वंचित रहना पड़ा। दिलचस्प है कि विरोधियों ने नेहरू पर पाकिस्तान और चीन के प्रति नरमी दिखाने का आरोप लगाया, मानो वे शांति पुरस्कार पाना चाहते हों। नवाचार से विवाद तक इसका ताजा उदाहरण है लद्दाख के पर्यावरणविद् और शिक्षक सोनम वांगचुक, जिन्हें 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण शिक्षा सुधार के उनके प्रयासों और 'आइस स्तूप' जैसे सामुदायिक नवाचारों के लिए दिया गया था । उस समय पूरे देश में उनके पुरस्कार को गर्व की दृष्टि से देखा गया। हाल के वर्षों में वांगचुक ने लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर मुखर आलोचना की। इसके परिणामस्वरूप उन पर पाबंदियाँ लगीं और सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ी, जो दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त व्यक्तियों की स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विडंबना यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति अपने देश में विवादों का केंद्र बन जाते हैं। कुछ संगठन, मीडिया और व्यक्तियों द्वारा आलोचना की गई, जिससे न केवल पुरस्कार विजेता की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक छवि पर भी छाया पड़ती है। भारत में और भी ऐसे नाम हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला लेकिन वे आगे चलकर विवादों के घेरे में आ गए । अरविंद केजरीवाल (2006) को सूचना के अधिकार आंदोलन और भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला। प्रारंभ में 'युवा नायक' कहे जाने वाले केजरीवाल राजनीति में प्रवेश के बाद आलोचना का विषय बन गए। रवीश कुमार (2019) खोजी पत्रकारिता और लोकतांत्रिक संवाद को बचाने की प्रतिबद्धता के लिए जाने माने नाम हैं । एक ओर उन्हें 'सत्य की आवाज' कहा गया, तो दूसरी ओर उन्हें सरकार विरोधी पत्रकार बताकर आलोचना की गई। बेजवाड़ा विल्सन (2016) को सिर पर मैला ढोने के खिलाफ उनके काम को अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिली, लेकिन विरोधियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे भारत की छवि को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं।

मदर टेरेसा (1962) को गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार और बाद में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। पर भारत में एक वर्ग ने उन्हें 'धर्मांतरण एजेंडे' से जोड़कर कठोर आलोचना की। साहित्य में नोबेल विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर (1913) और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (1998) भी अपनी वैचारिक दृढ़ता के कारण तीखी आलोचनाओं से अछूते नहीं रहे। टैगोर पर यह आरोप लगाया गया कि 'जन गण मन' ब्रिटिश सम्राट की प्रशंसा में लिखा गया, जबकि विद्वानों ने इसे निराधार बताया। इसी तरह अमर्त्य सेन पर विश्वभारती की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के आरोप लगे, किंतु वे अब तक न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए और अधिकतर राजनीतिक विवाद ही माने गए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जैसे-जैसे भारतीय समाज और राजनीति ध्रुवीकृत होती गई है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की स्वीकार्यता भी विभाजित हो गई है। आज स्थिति इतनी विकट हो चली है कि कट्टर भावनाओं से संचालित संकीर्ण धार्मिक दृष्टि, सेवा और करुणा जैसे निष्कलुष मानवीय मूल्यों को भी शंका और अविश्वास के घेरे में देखती है। इसके विपरीत, गांधीवादी कार्यकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिलने पर सर्वत्र

प्रशंसा हुई। भूदान आंदोलन के लिए विनोबा भावे को में सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को जनसेवा और लोकतंत्र के लिए पुरस्कृत किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के लिए सम्मानित हुए। यह दिखाता है कि जब कोई भारतीय गांधीवादी मूल्यों पर आधारित कार्य करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और देश में व्यापक समर्थन मिलता है। यह भी विचारणीय है कि शिक्षा और आपदा-सेवा में सक्रिय आरएसएस या उसके संगठनों का नाम अब तक रमन मैग्सेसे या नोबेल जैसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में क्यों नहीं आया ? आरएसएस को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार न मिलने के कई कारण हैं- जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ लोकतंत्र, मानवाधिकार और उदारवाद को प्राथमिक मानदंड मानती हैं, जबकि आरएसएस का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एजेंडा इससे मेल नहीं खाता। वैश्विक मीडिया में आरएसएस की छवि बहुसंख्यकवादी और अल्पसंख्यक-विरोधी संगठन की है।

जब किसी देश के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अपने ही समाज में विवाद का विषय बन जाते हैं, तो इससे उस देश की छवि धूमिल होती है। अमर्त्य सेन, रवीश कुमार या सोनम वांगचुक जैसे लोग दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन उन्हें वैचारिक विरोध का प्रतीक बताकर अक्सर हाशिए पर धकेलने के प्रयास होते रहते हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि हम अपनी ही उपलब्धियों को सम्मान देने में असमर्थ हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समितियाँ आम तौर पर धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों को सम्मानित नहीं करतीं। इसके विपरीत, मुस्लिम महिलाओं और पीड़ित समुदायों को अधिक मंच मिलता है–जैसे मलाला युसुफजई (पाकिस्तान) और शिरीन इबादी (ईरान)। आरएसएस जैसी संस्थाएँ, जिनका भारत में बड़ा सामाजिक नेटवर्क है, अपनी संकीर्णताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय मान्यता से वंचित हैं। यह स्थिति भारत की बहुलता और लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। यदि हम सचमुच वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आलोचकों और विचार-विरोधियों को भी उतनी ही गरिमा देनी होगी जितनी अंतरराष्ट्रीय समुदाय देता है। यद्दपि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की राजनीति हमेशा निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि पश्चिमी दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताओं से प्रभावित होती रही है तथापि महात्मा गांधी से लेकर सोनम वांगचुक तक की यह यात्रा हमें बताती है कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं हैं, वे एक देश की वैश्विक छवि का भी प्रतीक हैं। गांधी और नेहरू को पुरस्कार से वंचित रखना और सोनम वांगचुक जैसे विजेताओं की आलोचना करना, कतिपय संगठनों की संकीर्ण मानसिकता- यह सब भारत के लिए गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। जब तक हम अपने ही नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक भारत की लोकतांत्रिक छवि अधूरी ही रहेगी।

वायुसेना दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

साहस, समर्पण और शक्ति का संगम भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर वायुसेना अपनी शक्ति, शौर्य और तकनीकी उत्कृष्टता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करती है। इस मौके पर आयोजित भव्य एयर शो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और सामर्थ्य का प्रतीक बन जाता है। आसमान में वायुवीरों के करतब, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के समकालिक युद्धाभ्यास को देखकर हर दर्शक रोमांच और गर्व से भर उठता है। वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल, मिग-29, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भारतीय आकाश को सुरक्षित रखने की अभेद्य शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं सारंग जैसे हेलीकॉप्टरों के शो स्टंट्स, प्रचंड और ध्रुव जैसे लाइट और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स, सी-295, अपाचे, डकोटा, चेतक और जगुआर जैसी भारी मशीनें वायुसेना की बहुपक्षीय क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। इन एयरक्राफ्ट की उच्च तकनीकी क्षमताएं न केवल देश की सुरक्षा की गारंटी हैं बल्कि इसे वैश्विक मंच पर सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाती हैं। भारतीय वायुसेना दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि युवाओं को इस गौरवशाली सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। एयर शो के माध्यम से युवा पीढ़ी वायुसेना की चुनौतीपूर्ण, साहसिक और सम्मानजनक भूमिका के बारे में जानती है और उनके मन में देश सेवा के प्रति उत्साह जागृत होता है। आज भारतीय वायुसेना न केवल सीमा रक्षा में सक्षम है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता देने में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। यह स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना की समर्पित सेवा, साहस और तकनीकी दक्षता का उत्सव है, जो हमें यह याद दिलाता है कि भारत के आकाश में स्वतंत्रता, सुरक्षा और गौरव का सूर्य सदैव चमकता रहेगा।

भारतीय वायुसेना में इस समय राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, आरपीए 50, मिग-27, मिग-29 के अलावा हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनूक, चेतक, चीता, एमआई-8, एमआई-17, एमआई-26, एमआई-25 एचएएल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एचएएल रुद्र इत्यादि अत्याधुनिक विमान शामिल हैं, जो किसी भी विकट स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना होने का गौरव हासिल है। देश की करीब 24 हजार किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना पूरी मुस्तैदी के साथ निभाती रही है और वायुसेना के बेड़े मेंदमदार लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा अत्याधुनिक मिसाइलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, जिनके कारण हमारी वायुसेना अब पहले के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली हो चुकी है। अब हम हवा में पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो चुके हैं तथा दुश्मन की किसी भी तरह की हरकत का अधिक तेजी और ताकत के साथ जवाब देने में सक्षम हैं।

भारत के मुकाबले चीन के पास भले ही दो गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान हैं, भारत से दस गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर हैं लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार चीनी वायुसेना भारत के मुकाबले मजबूत दिखने के बावजूद भारत का पलड़ा उस पर भारी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक गिनती और तकनीकी मामले में भले ही चीन

सहित कुछ देश हमसे आगे हो सकते हैं लेकिन संसाधनों के सटीक प्रयोग और बुद्धिमता के चलते दुश्मन देश सदैव भारतीय वायुसेना के समक्ष थर्राते हैं। भारत के मिराज-2000 और एसयू-30 जैसे जेट विमान ऑल-वेदर मल्टीरोल विमान हैं, जो किसी भी मौसम में और कैसी भी परिस्थितियों में उड़ान भर सकते हैं। मिराज-2000, मिग-29, सी-17 ग्लोबमास्टर, सी-130जे सुपर हरक्यूलिस के अलावा सुखोई-30 जैसे लड़ाकू विमान करीब पौने चार घंटे तक हवा में रहने और तीन हजार किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40-70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम सी-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट भी वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। चिनूक और अपाचे जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी वायुसेना की मजबूत ताकत बने हैं। इनके अलावा भारत के पास दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम 952 मीटर प्रति सैकेंड की रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइलों सहित कई अन्य घातक मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक क्षमता से दुश्मन देश थर्राते हैं।

भारतीय वायुसेना की जाबांजी के अनेक किस्से दुनियाभर में विख्यात हैं। हमारी वायुसेना चीन के साथ एक तथा पाकिस्तान के साथ चार युद्धों में अपना पराक्रम दिखा चुकी है। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और तब इसका नाम था 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स'। 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध में रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय वायुसेना पर आर्मी का ही नियंत्रण होता था। इसे एक स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिलाया था इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर-इन-चीफ सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट ने, जो हमारी वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल बने थे। 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स' की स्थापना के समय इसमें केवल चार एयरक्राफ्ट थे और इन्हें संभालने के लिए कुल 6 अधिकारी और 19 जवान थे। आज वायुसेना में डेढ़ लाख से भी अधिक जवान और हजारों एयरक्राफ्ट्स हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वायुसेना को अलग पहचान मिली और 1950 में 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स' का नाम बदलकर 'इंडियन एयरफोर्स' कर दिया गया। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी इंडियन एयरफोर्स के पहले भारतीय प्रमुख थे। उनसे पहले तीन ब्रिटिश ही वायुसेना प्रमुख रहे। इंडियन एयरफोर्स का पहला विमान ब्रिटिश कम्पनी 'वेस्टलैंड' द्वारा निर्मित 'वापिती-2ए' था। बहरहाल, भारतीय वायुसेना ने समय के साथ बहुत तेजी से बदलाव किए हैं और काफी हद तक कमियों को दूर भी किया गया है।

लोकलुभावनवाद

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षिका हैं।

लोकतंत्र की राह में छिपा संकट

विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में लोकलुभावनवाद एक ऐसा शब्द बनकर उभरा है, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दिशा और दशा को गहराई से प्रभावित किया है। यह न केवल विकास नीतियों को प्रभावित करता है बल्कि दीर्घकालीन स्थिरता और संतुलन पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करता है। लोकलुभावनवाद की मूल प्रवृत्ति जनता के तात्कालिक हितों और भावनाओं को भुनाकर राजनीतिक लाभ लेना है। यह प्रवृत्ति हर उस समाज में दिखाई देती है, जहाँ सामाजिक असमानता, बेरोज़गारी, आर्थिक संकट या वैश्विक अनिश्चितताओं का दबाव अधिक होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह लोकलुभावनवाद एक स्थायी राजनीतिक रणनीति का रूप ले लेता है और शासन की प्राथमिकताओं को दीर्घकालीन सुधारों और स्थिर नीतियों से भटकाकर तात्कालिक राहत और वोट बैंक की राजनीति तक सीमित कर देता है।

पिछले कुछ दशकों में दुनिया के अनेक हिस्सों में लोकलुभावन नीतियों का प्रभाव बढ़ा है। यूरोप और अमेरिका में दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टियाँ और नेता उभरकर सामने आए हैं जिन्होंने प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और वैश्वीकरण को निशाना बनाकर आम जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार, लातिन अमेरिकी देशों में भी वामपंथी और राष्ट्रवादी लोकलुभावन नेता आर्थिक असमानताओं और गरीबी को मुद्दा बनाकर सत्ता तक पहुँचे। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भी लोकलुभावनवाद की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मुफ्त योजनाएँ, नकद हस्तांतरण, सब्सिडी और तात्कालिक राहत प्रदान करने वाली नीतियाँ आम जनता को तत्काल लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन दीर्घकालीन आर्थिक संरचना को अक्सर कमजोर कर देती हैं।

आर्थिक दृष्टि से लोकलुभावनवाद का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह उत्पादकता, निवेश और रोजगार सृजन के वास्तविक सुधारों से ध्यान हटाकर तात्कालिक उपभोग पर केंद्रित कर देता है। उदाहरणस्वरूप, जब सरकारें जनता को खुश करने के लिए अल्पावधि में बड़े पैमाने पर मुफ्त अनुदान और योजनाएँ लागू करती हैं, तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है और मुद्रास्फीति का दबाव भी बढ़ सकता है। इससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्टों में यह चिंता कई बार व्यक्त की गई है कि यदि विकासशील देश दीर्घकालीन उत्पादक निवेश के बजाय लोकलुभावन योजनाओं पर अत्यधिक निर्भर हो जाएँ, तो उनकी अर्थव्यवस्था स्थायी संकट की ओर बढ़ सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से भी लोकलुभावनवाद कई समस्याएँ उत्पन्न करता है। यह लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन और जवाबदेही की भावना को कमजोर कर देता है। जब नेता केवल बहुसंख्यक भावनाओं को भुनाकर सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं, तो अल्पसंख्यकों और हाशिये के वर्गों की उपेक्षा होने लगती है। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम होता है। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि कई देशों में चुनावी राजनीति 'हम बनाम वे' की मानसिकता को और अधिक गहरा कर रही है, जो लोकतंत्र के स्वस्थ भविष्य के लिए खतरा है।

लोकलुभावनवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू वैश्विक व्यवस्था से उसका टकराव है। आज के दौर में कोई भी देश अकेले नहीं चल सकता। आर्थिक सहयोग, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। किंतु लोकलुभावन राजनीति अक्सर राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद को बढ़ावा देती है। 'देश पहले' की सोच तात्कालिक रूप से जनताको आकर्षित करती है, लेकिन लंबे समय में यह वैश्विक सहयोग और आर्थिकप्रगति को नुकसान पहुँचाती है। उदाहरणस्वरूप, अमेरिका में ट्रंप प्रशासनने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति अपनाकर वैश्विक सहयोग की धारा को

कमजोर किया था, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत की दृष्टि से लोकलुभावनवाद का प्रश्न और भी गहन हो जाता है। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ अब भी गरीबी, बेरोज़गारी और सामाजिक असमानता बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ऐसे में लोकलुभावन नीतियाँ आम जनता को तात्कालिक राहत देती हैं और राजनीतिक समर्थन भी अर्जित करती हैं। परंतु यदि यह नीति-निर्माण का स्थायी आधार बन जाए, तो भारत की विकास यात्रा बाधित हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, जब राजनीतिक दल चुनावों से पहले मुफ्त बिजली, पानी, गैस या नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं का वादा करते हैं, तो यह जनता को तो तत्काल राहत देता है, लेकिन दीर्घकाल में सरकारी खजाने पर बोझ डालता है और संरचनात्मक सुधारों को पीछे धकेल देता है।

लोकलुभावनवाद का समाधान केवल आलोचना करना नहीं है, बल्कि इसे संतुलित करना है। लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, किंतु नीति-निर्माताओं की ज़िम्मेदारी यह है कि वे तात्कालिक राहत के साथ दीर्घकालीन विकास रणनीतियों पर भी ध्यान दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आधारभूत ढाँचे और तकनीकी नवाचार में निवेश करना ही किसी भी राष्ट्र को स्थायी विकास की ओर ले जाता है। यदि सरकारें केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझी रहेंगी, तो न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि सामाजिक सामंजस्य भी खतरे में पड़ सकता है।

आज वैश्विक अनिश्चितता के दौर में लोकलुभावनवाद से और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की आशंका से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन नए संकट पैदा कर रहा है और तकनीकी बदलावों ने श्रम बाजार को अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में यदि सरकारें और राजनीतिक दल केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए अल्पकालिक योजनाओं में व्यस्त हो जाएँ, तो भविष्य की पीढ़ियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत जैसे देश को तो विशेष रूप से इस खतरे को समझना होगा, क्योंकि यहाँ की विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण समाज किसी भी असंतुलन से गहरे प्रभावित हो सकते हैं।

लोकलुभावनवाद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है क्योंकि यह जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं से जुड़ा है। किंतु जब यह राजनीति और नीतियों पर हावी होने लगे, तो यह विकास की राह में बाधक बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि लोकलुभावनवाद को संतुलित और नियंत्रित ढंग से समझा जाए। तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना ही किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज की राजनीति और नीतियों का मूल्यांकन इस कसौटी पर होना चाहिए कि वे केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनाई गई हैं या वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सशक्त और समृद्ध भविष्य गढ़ने में सक्षम हैं। लोकलुभावनवाद से सावधानी और विवेक के साथ निपटना ही भारत और विश्व के लिए विकास की स्थायी कुंजी हो सकती है।

नपा को जिला प्रशासन से मिलेगी जमीन, मंजूरी मिलते ही शुरू होगा काम

करबला के पास बनेगा दो मंजिला फायर स्टेशन, ई-चार्जिंग स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टैंड

संजय द्विवेदी,

बैतूल। बैतूल में जल्द ही महानगरों की तर्ज पर फायर स्टेशन, ई-चार्जिंग स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने नगरपालिका को करीब 4 एकड़ जमीन आवंटित की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह जमीन करबला के पास स्थित है, जहां इनका निर्माण होगा। इसके लिए 15वें वित्त आयोग से करीब 2 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि फिलहाल बैतूल नगर पालिका के पास दो बड़ी और एक छोटी फायर ब्रिगेड हैं। जगह की कमी के कारण इन्हें नगरपालिका परिसर में ही खड़ा करना पड़ता है। यहां तक कि कर्मचारियों के लिए अलग से कोई कमरे की सुविधा भी नपा के पास उपलब्ध नहीं है। मुख्य गेट के पास एक अस्थायी जगह पर ही फायर कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी निभाते हैं और जैसे ही इमरजेंसी कॉल आता है, फायर ब्रिगेड मौके पर रवाना हो जाती है। यह स्थिति वर्षो से बनी हुई है और कर्मचारियों ने कई बार अलग फायर स्टेशन की मांग भी उठाई थी।

दो मंजिला बनेगा स्टेशन भवन - जिला प्रशासन द्वारा आवंटित जमीन पर बनने वाले फायर स्टेशन पर दो मंजिला भवन होगा, जहां कार्यालय, कंट्रोल रूम और फायर कर्मियों के लिए आवास की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा फायर वाहनों के लिए हाईटेंट, पानी की आपूर्ति की विशेष व्यवस्था तथा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म 70 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझाने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, फायर फाइटर्स को आधुनिक उपकरणों से लैस करने और उनके प्रशिक्षण की भी योजना है। उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की आगजनी की घटना पर तत्काल काबू पाया जा सके। नगर पालिका के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के निकायों में फायर स्टेशन बनने वाले हैं। जिसकी ड्राइंग और डिजाइन एक जैसी होगी और शासन द्वारा अलग से इसका बजट आवंटित किया गया है।

फायर स्टेशन नहीं, नपा में खड़े रहते हैं वाहन -शहर की सुरक्षा से जुड़ा सबसे अहम फायर सर्विस अभी वर्षों बाद भी बदहाल व्यवस्था में काम कर रहा है। न कर्मचारियों के लिए जगह, न ही फायर ब्रिगेड के लिए समुचित स्टेशन, ना ही प्रशिक्षित कर्मचारी , लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। फायर स्टेशन के लिए जमीन आवंटन और राशि स्वीकृति होने के बाद अब करबला के पास नया फायर स्टेशन का निर्माण किया जायेगा। जो आधुनिकतम व्यवस्थाओ से लैस होने के साथ-साथ यहां कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था रहेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि करबला रोड पर फायर स्टेशन, ई-चार्जिंग स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटन की कागजी कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त भोपाल द्वारा सभी नगर पालिकाओं को जमीन संबंधी जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ- फायर स्टेशन बनने से न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। शहर के बीचों बीच स्थित होने से आग लगने की घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी फायर वाहन शहर के बाहर बने स्टेशन से सुगमता से निकलकर मौके तक पहुंच सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और नुकसान कम किया जा सकेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि बैतूल जैसे शहर में जहां लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, वहां आधुनिक फायर स्टेशन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की संख्या भी बढ़ेगी और बैतूल नगर पालिका क्षेत्र के लिए चार से पांच गाडियां हमेशा उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही हर स्टेशन पर एक फायर ऑफिसर और एक फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति भी होगी।

इनका कहना है -

फायर स्टेशन, ई-चार्जिंग स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टैंड इन तीनों के लिए हमारे द्वारा जमीन आवंटन हेतु जिला प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है। करबला के पास जिला प्रशासन द्वारा जमीन चिन्हित की गई है, जो जल्द ही आवंटित हो जाएगी। नगरीय प्रशासन आयुक्त कार्यालय भोपाल से मंजूरी मिलने के बाद इन तीनों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया जाएगा।

सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का सारनी में हुआ भव्य स्वागत

बैतूल। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा एवं प्रदेश सचिव व आमला-सारनी विधानसभा प्रभारी समीर खान के छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान सारनी में आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सारनी जयस्तंभ चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारनी के अध्यक्ष किशोर चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाएं पहनाकर कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ कांग्रेस जन, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारनी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एवं एन.एस.यू.आई. के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष पटवारी का अभिनंदन करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ जयकारे लगाए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।

संक्षिप्त समाचार

स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनीं श्रीमती अमरीन खान

नर्मदापुरम , निप्र। जिला नर्मदापुरम के ग्राम हिरनखेड़ा की निवासी श्रीमती अमरीन खान ने स्व-सहायता समूह के माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। समूह से जुड़ने से पूर्व, श्रीमती खान अपने परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं। वे गृहणी थीं तथा परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। एकता आजीविका स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद श्रीमती खान ने विभिन्न चरणों में समूह से ऋण प्राप्त कर सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभिक दिनों में आमदनी कम रही, किंतु समय के साथ उनके कार्य की मांग बढ़ी और सिलाई से उन्हें पर्याप्त आय प्राप्त होने लगी। सिलाई कार्य में सफलता के बाद उन्होंने पुनः समूह से ऋण लेकर बकरी पालन प्रारंभ किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद श्रीमती खान ने समूह से प्राप्त ऋण की सहायता से किराना दुकान स्थापित की, जिसमें वे अपने आजीविका उत्पादों के साथ-साथ अन्य ब्रांडेड उत्पादों का भी विक्रय करती हैं। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रीमती अमरीन खान ने सिलाई, बकरी पालन और किराना दुकान जैसी आजीविका गतिविधियों के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ाई, बल्कि नारी शक्ति संकूल स्तरीय संगठन से ऋण, ष्टढ्ढस्र एवं बैंक ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय का विस्तार भी किया। श्रीमती खान की यह सफलता कहानी जिले की अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण है कि स्व-सहायता समूहों और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं।

लटेरी में कीटनाशक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

विदिशा , निप्र। विकासखण्ड लटेरी के आनंदपुर रोड स्थित मेसर्स अनन कृषि सेवा केन्द्र पर कीटनाशक औषधि विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री केएस खपेडिया ने बताया कि कीटनाशी निरीक्षक लटेरी द्वारा दुकान से नमूना लिया गया था। नमूने का परीक्षण जबलपुर स्थित कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला में कराया गया। जांच में पाया गया कि औषधि में निर्धारित अनुपात के स्थान पर 10.91% + 60.57% WP अनानक मौजूद था, जो मानकों के विपरीत है।इस आधार पर विक्रेता एवं निर्माता कंपनी के विरुद्ध कार्यालयीन आदेश के तहत विक्रय प्रतिबंध लगाया गया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर मेसर्स अनन कृषि सेवा केन्द्र का जारी कीटनाशक लाइसेंस क्रमांक 128, जारी दिनांक 11 सितम्बर 2015, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पट्टा पर जलाशय में मत्स्य पालन हेतु आवेदन आमंत्रित

विदिशा , निप्र। जनपद पंचायत कुरवाई की ग्राम पंचायत शेखपुर में स्थित तालाब घोसुआ जलाशय में सिंचाई जलाशय मत्स्य पालन नीति के तहत 10 वर्षी ए मत्स्य पालन विकास के लिए पट्टा पर देने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुरवाई जनपद पंचायत सीईओ ने बताया कि जनपद के स्वामित्व का जलाशय तालाब का जल क्षेत्र 61.31 हेक्टेयर है ।वंशानुगत मछुआ जातिअनुसूचित जनजातिअनुसूचित जाति,पिछडा वर्ग,सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति यदि उक्त प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार मछुआ स्वसहायता समूह मछुआ समूह को दिया जावेगा । जलाशय की पट्टा राशि मत्स्य पालन नीति 2008 के तहत निर्धारित की जावेगी। आवेदन पत्र एवं विस्तृत नियम,शर्तो जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत कुरवाई,सहायक संचालक मत्स्योस्द्योग जिला विदिशा में देखी जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खोवा बनाने वाली फर्मों का किया निरीक्षण

बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के मार्गदर्शन में मंगलवार को मुलताई स्थित खोवा बनाने वाली फर्मों का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा दल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान दल ने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया और खाद्य कारोबार कर्ताओं को साफ एवं सुरक्षित मिठाइयों के निर्माण के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कारोबार कर्ताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई बनाए रखने संबंधी हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान जहां कमियां पाई गईं, वहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(2) के तहत नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान अभिहित अधिकारी शैलेंद्र बडोनिया के मार्गदर्शन में सतत जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश, भोपाल भेजा जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संजीवनी क्लीनिक के सामने होगा सुंदर परिसर निर्माण

परिसर में पंच समाज के पांच संतों की पांच प्रतिमाएं लगेंगी

बैतूल/ मुलताई। इंदिरा गांधी वार्ड मुलताई में निर्माणाधीन संजीवनी क्लिनिक के सामने स्थित रिक्त भूमि पर पंच समाज के संतों और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी । नगर पालिका मुलताई, इस स्थल पर सुंदर बगीचे का निर्माण भी करावेगी, जिसका भूमि पूजन आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विधायक चंद्रशेखर देशमुख एवं नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर, भाजपा नेता नमन अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। भूमि पूजन अतिथियों ने धार्मिक रीति रिवाज एवं पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस अवसर पर भाजपा पार्षद, जनप्रतिनिधि, नगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गड़ेकर ने कहां की नगर पालिका संजीवनी परिसर भूमि पर एक सुंदर परिसर विकसित करेगी, जिसमें प्रतिमाओं के साथ बैठक स्थल, बगीचा और शेड का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि यह स्थल समरसता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा।

भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि संत रविदास, मातग ऋषि की लगेगी प्रतिमा-उक्त परिसर में पंच समाज के पांच महान संत-महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें भगवान गौतम बुद्ध, सुफल भगत, महर्षि वाल्मीकि, मातंग ऋषि और संत रविदास महाराज शामिल हैं। इन महापुरुषों ने समाज में समानता, मानवता और करुणा का संदेश दिया था। प्रतिमाओं की स्थापना का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में समाज सुधारकों की शिक्षाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में राजा चंडालिया, पंकज चंडालिया, अर्जुन पिपले, संदीप रगड़े, कुलदीप पहाड़, गणेश बडौदे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पंच समाज के सदस्यों ने भूमि पूजन के दौरान जयघोष करते हुए संतों की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लिया।

10 दिनों में ठेकेदार को पूर्ण करना होगा होगा संजीवनी क्लीनिक का कार्य.-नगर पालिका मुलताई द्वारा 24 लाख रुपए की लागत से इंदिरा गांधी वार्ड में बनाए जाने वाली संजीवनी क्लिनिक का निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूर्ण होना था आज 3 वर्ष पूर्ण होने को है इसके बावजूद भी निर्माण कार्य अधूरा है। निर्माण में लेटलतीफी पर नगर पालिका औपचारिकता निभाने रही इधर ठेकेदार को नोटिस भी जारी करते रहे और उधर समय सीमा भी बढ़ते रही वाल्मीकि जयंती पर संजीवनी क्लिनिक पहुंचे विधायक चंद्रशेखर देशमुख, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर काम पूरा न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने 10 दिनों में कार्य पूर्ण करने का कहां है अन्यथा ठोस कार्रवाई करने को कहा है।

इनका कहना...

ठेकेदार को संजीवनी क्लीनिक का कार्य 10 दिन में पूर्ण करने का आदेश दिया गया है और 10 दिन में कार्य पूर्ण न होने पर ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

महेश शर्मा, उपयंत्री नगर पालिका मुलताई

खेत में दिखा जंगली जानवर, तेंदुए की आशंका

वन विभाग ने तेंदुए के पंजों के निशान होने से इनकार किया, लकड़बग्घे की संभावना

हरदा, निप्र। हरदा जिले के रहटगांव वन परिक्षेत्र के सिंधखेड़ा गांव में रविवार शाम एक खेत में जंगली जानवर देखे जाने की सूचना मिली। ग्रामीणों को आशंका थी कि यह तेंदुआ हो सकता है। यह घटना भागवत सिंह सिंघा के खेत में हुई। ग्राम नकवाड़ा के उपसरपंच अरुण राजपूत ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम के साथ उपसरपंच राजपूत और ग्राम कोटवार सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।

वन विभाग की टीम ने खेत के अंदर पंजों के निशान देखे। इन निशानों में आगे की तरफ नाखून स्पष्ट दिख रहे थे। मोबाइल से तस्वीरें ली गई और उनकी तुलना तेंदुए के पंजों के निशानों से की गई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर दिनेश शर्मा ने बताया कि जांच के बाद पुष्टि हुई कि मिले हुए पंजे के निशान तेंदुए के नहीं थे। इसके बावजूद, वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी।

कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई कि लोग रात में बाहर निकलने से बचें और सतर्क रहें। डिप्टी रेंजर शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह दोबारा मक्का के खेत में सर्चिंग कर जांच की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई कि खेत में लकड़बग्घा आया होगा। सिंधखेड़ा गांव में एक खेत में जंगली जानवर देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शाम को खेत में एक जानवर देखा, जिसके बाद उन्हें तेंदुए के होने की आशंका हुई। यह घटना ग्राम सिंधखेड़ा में भागवत सिंह सिंघा के खेत में हुई। अरुण राजपूत (मो. 9933906072) ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम के साथ उप सरपंच अरुण राजपूत और ग्राम कोटवार भी मौजूद थे।मौके पर टीम ने खेत के अंदर पंजे के निशान देखे। इन निशानों में आगे की तरफ नाखून स्पष्ट दिख रहे थे। मोबाइल से तस्वीरें ली गईं और उनकी तुलना तेंदुए के पंजों के निशानों से की गई।जांच के बाद वन विभाग ने पुष्टि की कि मिले हुए पंजे के निशान तेंदुए के नहीं थे। इसके बावजूद, वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी। कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई कि लोग रात में बाहर निकलने से बचें और सतर्क रहें।

फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थाई लाइसेंस हेतु दिशा निर्देश जारी

विदिशा , निप्र। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशुल गुप्ता के द्वारा दीपावली पर्व पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के स्थाई लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसका अक्षर पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता के द्वारा अस्थाई आतिशबाजी अनुभूति के संबंध में गृह विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में जो जिला स्तर पर एसओपी जारी की गई है तदानुसार दुकानो हेतु स्थान का चयन व पूर्व मे ही सभी आवश्यक व्यवस्थाये कर ली जावें तथा स्थल का नजरी नक्शा व ले आउट भी तैयार कर ले, ताकि अनुज्ञप्तिधारियों को दुकान आवंटित करने में अनावश्यक परेशानी न हों। आपके द्वारा चयनित स्थानों की सूची 03 दिवस में जिला कार्यालय को भेजने।आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। जॉच के दौरान आयु सत्यापन स्कूली प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज से किया जा सकता है। आवेदक अत्यंत वृद्ध व मूक-बधिर न हो। आवेदक जिस स्थान पर विक्रय की अनुमति चाहता है वह उस नगर / ग्राम का निवासी होना आवश्यक है। किसी भी हाट बाजार में आतिशबाजी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। आवेदक के चरित्र / आपराधिक रिकार्ड संबंधी जांच संबंधित थाने से करायी जावे व थाना प्रभारी का स्पष्ट अभिमत लिया जावें। विस्फोटक निमय 2008 के नियम 86 के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त दो आतिशबाजी की दुकानों के मध्य आवश्यक सुरक्षा की दूरी 03 मीटर व रहवासी इलाके से 15 मीटर एवं किसी संरक्षित्त स्थलो से 50 मीटर की दूरी रखी जावें। उक्त अस्थायी दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होना चाहिये।आतिशबाजी को सुरक्षित,अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जायें ।आतिशबाजी विक्रय स्थान,दुकानो के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लेम्प / गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तीयों का प्रयोग नहीं होगा। बिजली के खुले तार आदि न हों। मास्टर स्वीच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये ताकि शार्ट सर्किट होने पर विधुत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जायेंआतिशबाजी विक्रय स्थल पर धूम्रपान करना व माचिस आदि रखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा तथा सफाई कर्मियों को भी निर्देशित किया जावे की वह आतिशबाजी विक्रय स्थल व उसके आस-पास

तीर्थदर्शन यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से प्रसन्न हुई श्रीमती मंजू मेहरा

नर्मदापुरम , निप्र। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले से 179 तीर्थ यात्रियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से हुआ। तीर्थ दर्शन योजना के तहत चयनित सभी तीर्थ यात्री 24 सितंबर को तिरुपति बालाजी दर्शन हेतु रवाना हुए थे। इन यात्रियों में नर्मदापुरम जिले की निवासी श्रीमती मंजू मेहरा ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। यात्रा पूर्व योजना के तहत तीर्थ दर्शन करने के अनुभवों को साझा करते हुए श्रीमती मेहरा बताती है कि यात्रा के दौरान उन्हें शासन की ओर से उपलब्ध कराई है सुव्यवस्थित चिकित्सा, भोजन एवं यात्रा सुविधाओं से वे अत्यंत संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जिले के अन्य तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात हुई, जो उनके लिए एक नया और सुखद अनुभव रहा।उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उन्हें तिरुपति बालाजी स्वामी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उनके जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है। तीर्थदर्शन यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को रेलमार्ग से आवागमन, आवास, भोजन, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

भाजपा राज में मौत का कफ सिरप,रोते बिलखते परिवारों के बीच पहुंचे कांग्रेस जिलाअध्यक्ष निलय डागा

कांग्रेस ने उठाई एक करोड़ मुआवजे की मांग

बैतूल। जिले के जामुन बिछुआ और कलमेश्वरा गांव में जहरीले सिरप से हुई मासूमों की मौत के बाद सोमवार 7 अक्टूबर को कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। श्री डागा ने इस हृदय विदारक घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबों को न अस्पताल में दवा मिलती है, न डॉक्टर दिखाते हैं। मासूमों की जान चली गई और आयुष्मान योजना ने सिर्फ कार्ड थमाए, इलाज नहीं दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैतूल जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में न

डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ, और ना ही जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने जिस जहरीले कफ सिरप को बांटने की अनुमति दी, वही मौत की वजह बन गया। एक मां को अपने मासूम को तड़पते देखना पड़ा और अंत में लाश उठानी पड़ी। फिर भी स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रशासन और जिम्मेदार नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा।

कांग्रेस ने मृतकों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने, दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पूरे मेडिकल सप्लाई चेन की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही श्री डागा ने कहा कि अगर सरकार ने आँखें नहीं खोलीं, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आदिवासी क्षेत्रों की जानलेवा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं जानलेवा हो चुकी हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए इलाज एक सपना बन चुका है। आयुष्मान योजना एक छलावा है, जिससे केवल बीमा कंपनियों का भला हो रहा है, मरीजों का नहीं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि भाजपा शासन में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रतिनिधि मनोज मालवे, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज देशमुख, उपब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र चाडढ़ा, युवा नेता विजय पारदी, अजय सोलंकी, अलकेश ठाकुर, रोहन रघुवंशी सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे।

पत्रकारों को चरणबद्ध ढंग से गढ़ते थे मामाजी

भोपाल। मामाजी पत्रकारों को चरणबद्ध ढंग से गढ़ते थे। पत्रकारिता के साथ वे जीवन के संस्कार भी सिखाते थे। उन्होंने हमेशा अपने उदाहरण से पत्रकारिता और लोक आचरण सिखाया। यह विचार वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय ने प्रख्यात संपादक मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी के जयंती प्रसंग पर विश्व संवाद केंद्र, मध्यप्रदेश की ओर से आयोजित विशेष व्याख्यान में व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन शिवाजी नगर स्थित माणिकचंद्र वाजपेयी सभागार, विश्व संवाद केंद्र में 7 अक्टूबर को किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में गिरीश जोशी उपस्थित रहे और अध्यक्षता लाजपत आहूजा ने की।

'मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी और पत्रकारिता का वर्तमान परिदृश्य' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गिरीश उपाध्याय ने कहा कि एक पत्रकार को समाचार पत्र के प्रकाशन की सम्पूर्ण जानकारी हो, इसकी चिंता वे करते थे। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनने के लिए भोपाल आया था लेकिन बाद में स्वदेश के साथ जुड़ गया। मुझे भोपाल से इंदौर में मामाजी के पास भेजा गया। उनके सान्निध्य में मैंने पत्रकारिता सीखी। मेरी पत्रकारिता पर उनकी गहरी छाप है।

इस अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव एवं लेखक गिरीश जोशी ने कहा कि भारत में पत्रकारिता को गढ़ने वाले महापुरुषों में मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी का प्रमुख नाम है। पत्रकारिता में उनका ध्येय राष्ट्रहित था। आज भी मामाजी को हम स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने आपातकाल लगने से पहले ही अपने एक संपादकीय में इसकी आशंका व्यक्त कर दी थी।

अध्यक्षीय उद्बोधन में विश्व संवाद केंद्र, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष लाजपत आहूजा ने कहा कि मामाजी भिंड में निजी महाविद्यालय में संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे लेकिन नियति उन्हें पत्रकारिता में ले आईद्य विश्व संवाद केंद्र ने मामाजी की जन्मशती पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया। मामाजी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निकट का संबंध था। एक ध्येयनिष्ठ संपादक के रूप में अटल जी मामाजी का बहुत सम्मान करते थे। मामाजी ने जो शब्द लिखे, उन्हें जिया भी। आप निस्पृह संपादक थे।

कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया गया। इसके साथ ही विश्व संवाद केंद्र के विशेषांक 'कन्वर्जन का खेल-निशाने पर जनजातीय' का विमोचन भी किया गया। विशेषांक का संपादन युवा पत्रकार एवं लेखक सुदर्शन व्यास ने किया है। कार्यक्रम संचालन युवा पत्रकार अदिति रावत ने किया और आभार ज्ञापन न्यास के सचिव लोकेन्द्र सिंह ने किया।

कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिबद्धता के लिए याद रहेंगे कॉमरेड रूप सिंह चौहान

भोपाल । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एटक के दिवंगत नेता कॉमरेड रूप सिंह चौहान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपने राज्य कार्यालय शाकिर सदन भोपाल में आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में प्रबुद्ध जनों ने दिवंगत कॉमरेड रूप सिंह चौहान को विभिन्न संस्मरणों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एटक के वरिष्ठ नेता कॉमरेड हरिद्वार सिंह , कॉमरेड डी डी शर्मा,कॉमरेड शिवशंकर मौर्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड प्रमोद प्रधान, कॉमरेड पूषण भट्टाचार्य, वरिष्ठ समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर,कर्मचारी नेता कॉमरेड वी के शर्मा, कॉमरेड गुण शेखरण,कॉमरेड नजीर कुरैशी, कॉमरेड आर सी बघेल,कॉमरेड यशवंत पुरोहित,कॉमरेड एस सी जैन,कॉमरेड पी एन वर्मा,कॉमरेड राम सरोज कुशवाह ,कॉमरेड संजय नामदेव, कॉमरेड रुद्रपाल यादव, कॉमरेड श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि कॉमरेड रूप सिंह चौहान ने मानवीय मूल्यों के लिए गहरी संवेदना,मेहनतकश जनता की वर्ग चेतना और मार्क्सवादी विचारधारा की समझ जीवन के अनुभवों से अर्जित की। अपने कर्मठ जीवन, जुझार तेवर, कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए प्रतिबद्धता के लिए कॉमरेड रूप सिंह चौहान हमेशा याद रहेंगे।श्रद्धांजलि सभा का संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने किया । श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत कॉमरेड रूप सिंह चौहान की पत्नी राधा चौहान,बेटी दीपशिखा चौहान अन्य परिवारजन,कर्मचारी नेता एस एस शाक्य सहित कई लोग उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से मिली राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीएम-किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी

*** जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि के 171 करोड़ रु. जमा**

*** 5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 85 करोड़ रु. का बजट भी मंजूर: शिवराज**

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। इस सादे समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहीं जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। आज की किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत अब तक कुल 4,052 करोड़ रु. की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदा से प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, हम सभी प्रभावित किसानों व अन्य लोगों को संकट से पार निकालेंगे, इसी कड़ी में एक कदम पीएम-किसान की किस्त की यह राशि बड़ी राहत है, जिससे किसान अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं व सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से हरसंभव मदद दे रही है, आगे भी जो प्रावधान है, उनके अनुरूप प्रभावित निवासियों को सहायता की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से लगभग 5100 घरों के क्षतिग्रस्त होने संबंधी जानकारी ज्ञापन के माध्यम से मिली है, जिनके पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 85.62 करोड़ रु. का विशेष प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है, जिसमें मूल सहायता राशि के अलावा शौचालय निर्माण व मनरेगा से भी राशि मिलेगी, ताकि लोग अपना घर फिर से बना सकें। साथ ही, राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी, जिससे कि प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता मिलेगी। शिवराज सिंह ने कहा कि खेती-बाड़ी फिर शुरू करने के लिए बीज, खाद व अन्य जरूरतें पूरी करने केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर हैं। जिसका खेत-उसकी रेत की नीति के तहत राज्य सरकार ने रेत बेचने के लिए अनुमति दे दी है, वहीं राज्य से प्रस्ताव मिलने पर एनडीआरएफ के तहत भी जरूरत होने पर राशि देने का प्रावधान हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी राज्य का प्रस्ताव मिलने पर राशि पीड़ित किसानों को उनके खाते में देने की व्यवस्था केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह व राज्य के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भी विचार रखें और केंद्र द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को गत दिनों उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र में किए दौरे के लिए भी धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वाल्मीकि जयंती पर किया नमन

प्रदेशवासियों को दी वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं,वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन

भोपाल(नप्र)। मुख्यमत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आदिकवि, महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के आदर्शों एवं मूल्यों को पवित्र रामायण के माध्यम से उन्होंने समूची दुनिया को मनुष्यता एवं मर्यादा की नई राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं समर्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमत्री डॉ. यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम और रामायण को देश के घर-घर पहुंचाकर अमर कर दिया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठजन भी उपस्थित थे। समाजजनों ने मुख्यमंत्री डॉ यादव का पुष्प गुच्छ, शाल श्रीफल, रामायण और महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र भेंटकर स्वागत अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी समाज-जनों से कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामभक्ति से आत्म विभोर होकर रामायण की रचना की। वही रामायण आज देश की जीवनधारा है। समाजजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

सप्रे संग्रहालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियां सम्मानित

भोपाल। ऐसी विभूतियां जो व्यापक समाज हित के लिए विशिष्ट और मूल्यवान कार्य कर रही हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित किया जाना समाज का दायित्व है। जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका कृतित्व तो वंदनीय है ही, इस पुनीत दायित्व के निर्वहन के लिए सप्रे संग्रहालय भी बधाई का पात्र है।

यह कहना है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी का। वे आज माधवराव सप्रे स्मृति समचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे ने की। सेज विवि के कुलाधिपति संजीव अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया।

मुख्यअतिथि तिवारी ने संग्रहालय से अपने निजी जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि मेरा 'गुरुकुल' है तो सप्रे संग्रहालय मेरा 'आंगन' रहा। अध्यक्षीय आसंदी से डॉ. विकास दवे ने कहा कि इस मंच से शिक्षा,ज्ञान परंपरा,पर्यावरण,पत्रकारिता आदि क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मानित किया गया है। भारत ही ऐसा देश है जो 'मन' को पढने वालों को सिर-आंखों पर बैठाता है। यह सम्मान भी इसी परंपरा की एक कड़ी है। विशिष्ट अतिथि संजीव अग्रवाल ने कहा कि सप्रे संग्रहालय ज्ञान का खजाना है।

सनातन वैष्णव परंपरा के प्रतीक हैं गांधी...

कार्यक्रम में महात्मा गांधी सम्मान से विभूषित वेद मर्मज्ञ आचार्य प्रभुदयाल मिश्र ने 'गांधीत्व एक सहयात्रा' विषय पर वक्तव्य देते हुए कहा कि गांधी सनातन वैष्णव परंपरा की पहचान हैं। इस कार्य के लिए बापू को आदि शंकराचार्य, तुलसी और स्वामी दयानंद के समकक्ष रखा जाना चाहिए। 'डॉ. हरिकृष्ण दत्त शिक्षा सम्मान' से सम्मानित शिक्षाविद् डॉ. सरोज गुप्ता ने संस्कृत श्लोकों के माध्यम से लोक साहित्य और संस्कृति की महत्ता बताई। आरंभ में संग्रहालय की ओर से समिति के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार अवस्थी एवं विवेक श्रीधर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ रामबल्लभ आचार्य रचित भाषा गीत की प्रस्तुति की गई। संचालन सप्रे संग्रहालय के निदेशक अरविंद श्रीधर ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अल्पना गिरी ने किया।

इनका हुआ सम्मान...

कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्येता आचार्य प्रभुदयाल मिश्र, भोपाल को 'महात्मा गांधी सम्मान' से विभूषित किया गया। शिक्षाविद डा. सरोज गुप्ता, सागर को 'डॉ. हरिकृष्ण दत्त शिक्षा सम्मान' से सम्मानित किया गया। 'डॉ. लक्ष्मीनारायण गुप्त महाकौशल पत्रकारिता पुरस्कार' जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार संजय साहू को प्रदान किया गया। इंदौर में शोध संदर्भ सामग्री के संचयन में तीन दशक से समर्पित कमलेश सेन, उद्घोषक संजय श्रीवास्तव तथा सुनील दुबे 'वृक्षमित्र' को 'कर्मवीर सम्मान' से सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ल को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 'रामेश्वर गुरु पुरस्कार' दिया गया।

निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागी पुरस्कृत...

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तपोनिष्ठ पं. सुंदरलाल श्रीधर की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष 'आजादी के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ता देश: वर्तमान परिदृश्य अपेक्षित प्राथमिकताएं' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से कुल 165 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिनमें से प्रथम तीन के अलावा तीन सांत्वाना पुरस्कार भी दिये गये। इनमें प्रथम - अक्षत पटेल,गाडरवारा,द्वितीय - शुभम सक्सेना, भोपाल तथा तीसरे स्थान पर मंजू महेडिया, भोपाल रहीं। इसके अलावा श्रुति दुबे, भोपाल, उमेश पंसारी,सीहोर तथा महक हिरवे,भोपाल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गये। पुरस्कार के तहत नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये गये।

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होने जा रहा है : पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत भाजपा केसरीमल सेनापति मंडल की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

धार । भाजपा जिला कार्यालय धार में मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत भाजपा केसरीमल सेनापति मंडल की एक दिवासीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला प्रभारी एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विशाल निगम भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा , जिला कोषाध्यक्ष मनीष प्रधान, मंडल संयोजक हुकुम लश्करी सह संयोजक राजेश हारोड़, रंजना राठौड़, अमित शर्मा महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष, निशा शर्मा मंचासीन रहे।

अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र एवं पित्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया गया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी की जन्म जयंती से 25 दिसंबर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक आयोजित होगा जिसमें जिला, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा । स्वदेशी सामान खरीदना और उसके लिए प्रोत्साहित करने सहित वोकल फार लोकल से आत्मनिर्भर भारत निर्माण कर सकें।

मनोज सोमानी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के मोदी सरकार

जनधन खाते के माध्यम से देश में 50 करोड़ से अधिक खाता खोले गए प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्राप्त हुआ । उज्ज्वला योजना से 10 करोड परिवार लाभान्वित हुए आयुष्मान भारत कार्ड से देश में 37 करोड लोगों ने मुफ्त में इलाज कराया देश में 80 करोड लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा 5 लाख तक निशुल्क इलाज करवा रही है। देश में अनेक जगह जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध करा रही है सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना से 12 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत देश में 90त्न गांव तक यह योजना पहुंच चुकी है। भारत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से 100 करोड़ लोग उपयोग कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत अनेक जन हितेषी योजना संचालित हो रही है साथ ही प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना से महिलाओं के सीधे खाते में राशि डाली जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की इन जन हितेषी योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होने जा रहा है।

कार्यशाला का संचालन मंडल महामंत्री अमित शर्मा ने किया। आभार रितेश अग्निहोत्री ने माना। जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।

फूप में पांच की मौत के मामले में ड्राइवर बदला

पुलिस की पूछताछ में खुला षड्यंत्र, वाहन मालिक ने रिश्तेदार को पैसे देकर झूठा चालक बताकर पेश किया

भिंड (नप्र)। भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 719 पर बीते सप्ताह हुए भीषण सड़क हादसे में अब चौंकाने वाला मोड़ आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों सहित गोताखोर की मौत हुई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि हादसे के असली आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक झूठे ट्रक चालक को पुलिस के सामने पेश कर दिया था। अब पुलिस ने वाहन मालिक सहित झूठा चालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरी घटना-यह हादसा 30 सितंबर की सुबह 11 बजे फूप थाना क्षेत्र के टेढ़ा पुलिया के पास हुआ था। पावई क्षेत्र के सोरा गांव निवासी सुनील बघेल अपनी पत्नी पपीता बघेल, पुत्री अंशु और पुत्र छोटे बघेल के साथ बाइक पर सवार होकर फूप कस्बे में रहने वाले अपने चाचा हवलदार सिंह के घर अष्टमी पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार मिनी ट्रक (कंटेनर) ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिवार के चारों सदस्यों की मौके पर मौत हो गई। इसी हादसे में पीछे से आ रहे भिंड शहर के गोताखोर भोला खान भी रौंदे गए, जिससे उनकी भी मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था।

रिश्तेदार को पैसे देकर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने कहा-पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान वाहन मालिक राहुल कुशवाहा ने खुद को बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदार कल्लू कुशवाहा को डेढ़ लाख रुपए का लालच देकर झूठा चालक बनाकर पुलिस के सामने पेश किया। कल्लू ने घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। हालांकि जब पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया।

सीसीटीवी से खुला राज-सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखा कि वाहन को स्वयं राहुल कुशवाहा चला रहा था, जिसने तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए बाइक सवारों को कुचला और मौके से भाग गया। फूप थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि वाहन मालिक ने अपराध से बचाने के लिए झूठी कहानी रच दी और पुलिस जांच को भ्रमित करने का प्रयास किया।

फिक्की फ्लो कार्ट प्रदर्शनी देहरादून में बाग प्रिंट कला का जलवा

*यूनेस्को अवॉर्डी मोहम्मद आरिफ खत्री के कार्य ने आगंतुकों का मोहा मन *उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी ने की सराहना

भोपाल। फिक्की (FICCI) द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर को देहरादून में आयोजित फ्लो क्राफ्ट बाज़ार प्रदर्शनी में देशभर से आए प्रतिष्ठित हस्तशिल्पियों ने अपनी पारंपरिक एवं नवोन्मेषी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में यूनेस्को अवॉर्डी बाग प्रिंट शिल्पकार श्री मोहम्मद आरिफ खत्री के कार्य को विशेष सराहना प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी ने प्रदर्शनी स्थल पर श्री खत्री एवं श्री मोहम्मद अली खत्री के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने बाग प्रिंट की पारंपरिक छपाई प्रक्रिया, प्राकृतिक रंगों के उपयोग एवं इस हस्तकला की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। श्रीमती धामी ने खत्री बंधुओं द्वारा प्रदर्शित कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए एक सुंदर बाग प्रिंट की सिल्क साड़ी क्रय की तथा इस पारंपरिक कला को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों की सराहना की।

प्रदर्शनी में श्री खत्री द्वारा बाग प्रिंट की साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, टेबल रनर एवं बांस से निर्मित चिक ब्लाइंड्स जैसी विविध कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गईं। प्राकृतिक रंगों एवं लकड़ी के ब्लॉक्स से की जाने वाली इस पारंपरिक छपाई कला ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया।

देहरादून में कला-प्रेमियों से प्राप्त सम्मान प्रेरणादायक

श्री मोहम्मद आरिफ खत्री, मध्यप्रदेश के धार जिले के बाग गाँव के निवासी हैं। बाग प्रिंट कला उनके परिवार में पीढ़ियों से प्रचलित है। यह शिल्पकला आज भारतीय हस्तकला की पहचान बन चुकी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही है।

इस अवसर पर श्री खत्री ने कहा कि देहरादून में कला-प्रेमियों द्वारा प्राप्त सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि जब समाज पारंपरिक कला को समझता और उसे सम्मान देता है, तो यह किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं होता।

शिवपुरी में तेज रफ्तार कार से 4 गायों की मौत

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी के थीम रोड पर सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठी गायों को टक्कर मार दी, जिससे चार गायों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उदय विलास होटल के पास हुई। गौसेवकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

5 अक्टूबर की घटना-गौसेवक आकाश तिवारी उर्फ अभिराम दास महाराज और अन्य गौ रक्षक मंगलवार को कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि यह घटना 5 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे हुई। एक ब्रीजा कार (एमपी 33 सी 7241) ने लापरवाही से चलाते हुए गायों को कुचल दिया।

राइट क्लिक

दो संगठन, एक सदी- 2

क्या 'राष्ट्र' और 'जन' का यह झगड़ा कृत्रिम नहीं है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हर विचार महत्वपूर्ण होता है। उसके जन्म के पीछे भी कुछ ठोस कारण होते हैं। अपने शुद्ध रूप में विचार शायद ही कभी मरता है। लेकिन अगर उसका राजनीतिक-सामाजिक एप्लीकेशन विफल हो जाए तो विचार महज कतिपय लोगों की बौद्धिक जुगाली भर रह जाता है। विचारों के इस संघर्ष को क्रिकेट की भाषा में समझें तो दो विचारों के मुकाबले में व्यावहारिकता की भूमिका अंपायर की होती है। दूसरे, मूल विचार यदि समय के साथ कदमताल नहीं कर पाए तो वह हाशिए पर चला जाता है, भले ही उसके अनुयायी इसे स्वीकार करें या न करें। कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में वैध रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पर कभी सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन उनके अनुषांगिक संगठनों जैसे कि सीपीआई (माओवादी), सीपीआई (मार्क्सवादी लेनिनवादी) पीपुल्स वॉर तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर पर प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी सशस्त्र विद्रोह के समर्थक हैं। उनका विश्वास संवैधानिक लोकतंत्र में नहीं है। जबकि आरएसएस पर उसकी स्थापना से लेकर अब तक तीन बार प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन हर प्रतिबंध के बाद आरएसएस की ताकत बढ़ती गई।

संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा और वामपंथियों की जनवादी विचारधारा की तुलना करते समय हमे इन घटकों का खास ध्यान रखना होगा। ये हैं- विचार की प्रासंगिकता, सामयिक सकारात्मक बदलाव और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उसकी व्यावहारिकता और लोकस्वीकार। संघी और वामी विचारों में में प्रतिबद्धता की कमी नहीं है, वैचारिक और लक्ष्यगत स्पष्टता है, सुगठित संगठन और कैडर भी है। एक का कार्यकर्ता स्वयंसेवक है तो दूसरे का कॉमरेड। हालांकि आरंभ में दोनो का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था, लेकिन आजादी के बाद दोनो ने बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया और इसी दायरे में अपना मार्च शुरू किया। वामपंथियों की सफलता यह रही कि उन्होंने गरीबों, मजदूरों और किसानों को अपनी राजनीति और क्रांति के आग्रहों के केन्द्र में रखा। उस हिसाब से नीतियां बनाने का दबाव बनाया। जबकि आरएसएस जो आरंभ में केवल हिंदुओं को सांस्कृतिक, सैनिक आधार पर संगठित करने का पैरोकार था, उसने भी अपनी राजनीतिक शाखा जनसंघ स्थापित की और तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष और कदाचित धर्म को हिकारत के भाव से देखने के आग्रह के खिलाफ बहुसंख्यकों को संगठित करना शुरू किया। हालांकि इसमें कुछ खतरे भी हैं।

अब जबकि दोनों अपने संघर्ष और परिवर्तनों के सौ साल पूरे कर रहे हैं तो यह तुलना अस्वाभाविक नहीं है कि यह देखें कि कौन कहां खड़ा है? हालांकि यह कोई मेडल जीतने की रेस नहीं है, और न ही इसमें कोई अंतिम फैसला दिया जा सकता है, फिर भी समीक्षक दृष्टि यह मांग करती है कि विचारों का धरातल पर सफलता का परिमाण क्या है, आज स्टैंडिंग क्या है और कल उनका भविष्य क्या है? सवाल यह भी है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था और जन केन्द्रित शासन प्रणाली का विचार लेकर बढ़ रहे कम्युनिस्ट अस्सीवें साल तक आते-आते हाशिए पर क्यों चले गए? 'जन' ने ही उन्हें ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी? उनका जन केन्द्रित विचार-आचार भारतीय जन में ही क्यों गहरी पैठ (यहां बात सीपीएम की नहीं है) नहीं बना पाया? क्या वामपंथी भारतीयों के मानस और उसकी गढ़न को ठीक से समझ नहीं पाए या फिर जनता से उसे अपने अनुकूल नहीं पाया? दूसरे, बौद्धिक तर्क-वितर्क आम जनता के गले तब तक नहीं उतरते, जब तक आप उसे उसकी भाषा, मान्यताओं और आग्रहों के अनुरूप नहीं समझा पाते तथा जनता खुद उसे अपने हित में नहीं मानती। अन्यथा वो विचार एक व्यापक और सर्व समावेशी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन में नहीं बदल सकता। इसके लिए विचार की सरलता और बोध गम्यता भी जरूरी है। वामपंथी विचारधारा इस मोर्चे पर व्यावहारिक दृष्टि से जड़ लगती है। वामपंथ में प्रतिबद्धता पर बहुत ज्यादा जोर है, वह ठीक भी है, लेकिन विचार अगर व्यावहारिता से संगति नहीं बिठा पाता तो वह जड़ता के स्पैम बॉक्स में चला जाता है। यूं वामपंथी संघियों की 'अबौद्धिक' कहकर आलोचना करते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो संघियों की कथित 'अबौद्धिकता' में भी व्यावहारिकता और सहज बोध का भाव ज्यादा है। इसी कारण उनकी पहुंच और स्वीकार्यता लोगों के बीच लगातार बढ़ती रही है।

दरअसल देश में जातिवादी और सम्प्रदायवादी राजनीति के उभार और बदलती वैश्विक व्यवस्था ने भी कम्युनिस्टों को दुविधा में डाला है, क्योंकि इससे उनकी 'अंतरराष्ट्रीय भाईचारे' की राजनीति भी मुश्किल में पड़ गई है। ऐसा ही मामला सोशल इंजीनियरिंग का भी है। इसकी तुलना संघ से करें तो संघ के सर्वोच्च पद सरसंघचालक पर भी सवर्ण और खासकर ब्राह्मण ही रहे हैं। संघ में कभी कोई दलित भी सरसंघचालक बनेगा, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन संघ ने जातीय उत्थान के प्रयोग अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा में बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि अगड़ों के अलावा पिछड़ों और अब दलितों और आदिवासियों में भी संघ विचारधारा की स्वीकार्यता पहले से बढ़ी है। जबकि जिन राज्यों में कम्युनिस्ट कभी बहुत ताकतवर थे, वहां भी उनकी चादर सिकुड़ती जा रही है। वो इस सच्चाई को स्वीकार करने अभी भी तैयार नहीं हैं कि भारतीय जीवन शैली में धर्म की महत्ता सनातन है। उसका उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया जाए या नहीं, अथवा कितना किया जाए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे खारिज तो कदापि नहीं किया जा सकता। संघ ने अपनी नाव उसी दरिया में उतार दी है, जिसे कम्युनिस्टों ने प्रतिगामी और समाज के लिए अफीम निरूपित किया था। हालांकि माकपा घुमा-फिराकर इसे मंजूर कर रही है।

वामपंथियों द्वारा किसान-मजदूरों के शोषण का विरोध बिल्कुल जायज है। लेकिन इसके लिए पूंजी और पूंजीपतियों का अंध विरोध बेतुका है। इसी तरह सभी संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण का आग्रह भारत में इसलिए फेल हो गया, क्योंकि सरकारी तंत्र में कार्यसंस्कृति, जवाबदेही और बुनियादी ईमानदारी का अभाव है। कार्यसंस्कृति विहीन कोई भी देश सफल नहीं हो पाया है। जिन देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कम्युनिज्म को अपनाया, उन्होंने भी धीरे-धीरे उससे पल्ला छुड़ा लिया और जिन गिने-चुने देशो में अभी भी साम्यवाद सत्ता में है, वह असल में साम्यवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और नस्लवाद का अजब प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष घालमेल है, जिसे ज्यादा से ज्यादा 'सत्तावाद' ही कहा जा सकता है।

संघ पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह समाज को विभाजित कर रहा है। मोटे तौर पर यह विभाजन हिंदू-मुस्लिम का है। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी दलीय लोकतंत्र में राजनीति का पौधा विभाजन के खाद-पानी पर ही पनपता है। फर्क केवल विभाजन के प्रकार और प्राथमिकता का है। मसलन आप यह विभाजन आर्थिक, धार्मिक,जातीय, क्षेत्रीय या नस्ल अथवा अन्य किसी आधार पर करना चाहते हैं। यूं सभी राजनीतिक दल देश की एकता की बात करते हैं, लेकिन सत्ता स्वार्थ के चलते व्यवहार में इसकी जड़ खोदने में संकोच नहीं करते। अब तो जाति, धर्म या वर्ग विशेष की राजनीति करने को 'न्याय की आकांक्षा' के रूप में पेश किया जाता है। कम्युनिस्टों ने वर्ग विभाजन की सियासत शुरू की जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन जवाब में संघ ने धर्म विभाजन और सपा, बसपा जैसे दलों ने जाति विभाजन का कार्ड खेलकर वर्गवादी राजनीति को हाशिए पर पहुंचा दिया। इसका कोई माकूल तोड़ वामपंथियों के पास नहीं है। अब वह मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि सभी दल देश की एकता-अखंडता की चिंता किए बगैर समाज को माइक्रो स्तर तक विभाजित करने में लगे हैं ताकि किसी तरह सत्ता हथियाई जा सके या फिर मिली सत्ता पर काबिज रहा जा सके।

उधर संघ जिस सामाजिक समरसता की बात करता है, उसका भविष्य क्या है? क्या हिंदुत्व के वर्चस्व की छाया तले अन्य समाजों धर्मों का मान-सम्मान कायम रह सकता है? रहेगा तो कैसे ? दूसरे, अन्य धर्मों के गुण-दोषों पर टीका करने से ज्यादा गंभीर मामला स्वयं हिंदू धर्म के आंतरिक चुनौतियों और अंतर्विरोधों का है। इनसे निपटना और सभी हिंदुओं को एक न्यूनतम समान स्तर पर लाना संघ के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर 'हिंदू' होना ही निदान है तो दूसरे धर्मों से 'घर वापस' आए लोगों के हिंदू धर्म में समुचित और सम्मानजनक पुनर्वास का दीर्घकालीन रोड मैप क्या है?

एक और अहम मुद्दा समयानुकूल बदलाव का है। विरोधियों की नजर में संघ मनुवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का हामी है, लेकिन हकीकत में संघ समय के अनुसार खुद को बदलता रहा है। कारण जो भी हों, यह प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक स्तर भी है। हालांकि अभी भी संघ को लेकर दलित और आदिवासी समाज में कुछ कुशंकाएं हैं। दूसरे, भारतीयता, भारतीय सोच व दर्शन को खारिज कर कोई संगठन या आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि हमे पश्चिम को पूरी तरह नकार देना चाहिए। लेकिन कोई भी विचार और उसका राजनीतिक एप्लीकेशन भारतीय परिस्थितियों और मान्यता के दायरे में ही सफल हो सकता है। बौद्धिकता मनुष्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और सभ्यतागत विकास के लिए जरूरी है, लेकिन बौद्धिकता को ही सर्वस्व मान लेना महाचूक है। क्योंकि आम आदमी का दैनंदिन जीवन केवल बुद्धि से संचालित नहीं होता। उसमें और भी बहुत से घटक काम करते हैं। जीवन को देखने-समझने और उसके रहस्यों को जानने, सुलझाने और भौतिक रूप से सुखी जीवन जीने की दृष्टि से वैज्ञानिक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां आध्यातत्मिकता और धार्मिक आस्था पाताल जैसी गहरी है, वहां इन बातों को खारिज कर आमूलचूल परिवर्तन की बात करना बेकार है। भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था और बुराई है। जातियां भी वर्ग में बंटी हैं, इसलिए वर्गवाद का कोना पकड़कर दूर तक नहीं जाया जा सकता। संघ परंपरा और आस्थागत बातों को ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन उसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समान महत्व देना चाहिए। इससे उसकी ताकत और बढ़ेगी। प्राचीन पर गौरव अच्छी बात है, लेकिन अर्वाचीन का स्वीकार भी अनिवार्य है, हम 21 वीं सदी में जी रहे हैं और समूची मानव सभ्यता जिस दिशा में जा रही है, वहां यांत्रिकता की गुलामी के खतरे बढ़ रहे हैं।

प्रसंगवश यहां एक और सेवा संगठन की बात करना उचित होगा। ये है कांग्रेस सेवा दल। इसकी स्थापना डॉ. नारायण सुब्बाराव हर्डीकर ने 28 दिसंबर 1923 को यानी आरएसएस के लगभग दो साल पहले की थी। वैसे हर्डीकर और संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार आपस में दोस्त थे और प्रशिक्षित चिकित्सक थे। लेकिन दोनो की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं। सेवा दल की स्थापना का उद्देश्य कांग्रेस की सर्वसमावेशी, मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के अनुरूप युवा कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना और विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के प्रोजेक्ट पर काम करना था। लेकिन देश में सेवा दल स्थापना की शताब्दी लगभग खामोशी से गुजर गई। छोटे-मोटे आयोजन जरूर हुए। अपनी स्थापना आरंभ के कुछ दशकों तक सेवा दल एक देश व्यापी और बहुत सक्रिय संगठन रहा। बाद में वह कांग्रेस की सत्ता केन्द्रित राजनीति का शिकार हो गया। जबकि उसे संघ की तर्ज पर कांग्रेस को वैचारिक ऊर्जा देने वाले संगठन के रूप में विकसित किया जा सकता था। कांग्रेस के इस अनुषांगिक संगठन की कमान अब लालजी देसाई के हाथों में हैं। बीच में खबर आई थी कि सेवा दल भी आरएसएस की तर्ज पर अपने सेवा प्रकल्प शुरू करेगा, जो 55 वर्ष पहले ही बंद हो गए थे। हालांकि व्यवहार वैसा कुछ होता दिखा नहीं। सेवा दल कांग्रेस का चुनाव टिकट पाने का एक जरिया बनकर रह गया है।

फिर मूल मुद्दे पर लौटें तो वैचारिक दृष्टि से राष्ट्र और जन का झगड़ा कृत्रिम ज्यादा है, क्योंकि 'जन' से ही 'राष्ट्र' बनता है और किसी भी 'राष्ट्र' में 'जन' ही रहते हैं। दोनों मिलकर संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करते हैं। इसके लिए सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टि भी जरूरी है। केवल भूगोल के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। यानी अगर आप 'जन' की बात करते हैं तो 'राष्ट्र कल्याण का ध्यान रखना ही होगा और राष्ट्र कल्याण तभी होगा, जब जन सुखी, समृद्ध होंगें।

प्राकृतिक एवं जैविक खेती को करें प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि उपज पर आधारित है। इसलिए सरकार का मूल लक्ष्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। हमें इन क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसर भी बनाने हैं। सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें हरसंभव मदद भी मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के पहले सत्र 'कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स' को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे ग्रामीण युवा आने वाले समय में कृषि उद्यमी बनें, इसके लिए हमें मिल-जुलकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि खेती को जैविक खेती की ओर ले जाना एक बड़ी चुनौती है, पर हमें यह चुनौती भी पार करनी ही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न अर्थात् मिलेट्स को प्रोत्साहन देकर इनकी उपज को लगातार बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य है, हमें इस दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे। किसानों को परंपरागत खेती से शिफ्ट कर उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन जैसे आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों की ओर लेकर जाना है। प्रदेश में केला, संतरा, टमाटर एवं अन्य उद्यानिकी की फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। हमें इनके स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण एवं बड़े बाजारों तक मार्केटिंग की व्यवस्था भी करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों में उर्वरक की खपत सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर ही होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो इस पर नियंत्रण जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में साप्ताहिक मार्केट, हाट बाज़ारों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की उपज का विक्रय सुनिश्चित करें। साथ ही किसानों को नकद फसलों की खेती के लिए समझाइश देकर प्रोत्साहित करें। इसके लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर जिलों में 100-100 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर उसका रिकार्ड रखें और उनकी प्राकृतिक खेती के लाभों का अध्ययन भी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों अर्थात् बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने गुना जिले में गुलाब की खेती किए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के किसानों ने बड़ा ही प्रगतिशील कदम उठाया है। प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों में भी गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जाये, जिससे गुलाब उत्पादन की खपत स्थानीय स्तर पर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन फसल की नीलामी रेट की सघन निगरानी भी रखें।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिया प्रेजेंटेशन

कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स सत्र का संचालन कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल ने किया और प्रेजेंटेशन दिया। इस सत्र में प्राकृतिक खेती के प्रचार, जलवायु अनुकूल फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता केंद्रित क्लस्टर, सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर और सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फसल अवशेष प्रबंधन, खाद एवं बीज व्यवस्था, सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान योजना, दुग्ध उत्पादन और गौशाला प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वर्णवाल ने फसल अवशेष प्रबंधन (पराली निष्पादन नियंत्रण) को सरकार की विशेष प्राथमिकता बताते हुए इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर्स को गांव-गांव कृषक संगोष्ठियों के आयोजन और हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं बेलर जैसे उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलों में स्वीकृत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

- **पांच जिलों में हो रहा कृषि एवं उद्यानिकी पर बेहतरीन काम** – सत्र में प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर्स ने अपने-अपने जिलों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख किया। गुना कलेक्टर ने गुलाब क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में बताया। हरदा कलेक्टर ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रोत्साहन किए गए प्रयासों की जानकारी दी। शाजापुर कलेक्टर ने खाद वितरण के लिए टोकन प्रणाली विकसित करने के बारे में बताया। श्योपुर कलेक्टर ने फसल अवशेष प्रबंधन (पराली निष्पादन नियंत्रण) की बेहतर व्यवस्था की जानकारी दी। खंडवा कलेक्टर ने जिले में सफलतापूर्वक गौशाला संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र के अंत में जिलों के कलेक्टर्स एवं कमिश्नर्स ने प्रदेश की कृषि उत्पादन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिए।

किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों के उपचार का पूरा व्यय शासन द्वारा किया जायेगा वहन : सीएम डॉ. यादव

- **नागपुर के अस्पतालों में की गई है बच्चों के उपचार की व्यवस्था**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किडनी संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के बच्चों का उपचार नागपुर के चिकित्सा संस्थानों में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों का अच्छे से अच्छा उपचार हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित एम्स अस्पताल, कलर्स हॉस्पिटल, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गेटवेल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज जारी है। कलेक्टर छिंदवाड़ा और बैतूल द्वारा बच्चों के परिवारों से सतत संपर्क रखते हुए आवश्यक सहायता दी जा रही है। भोपाल से भी बच्चों के उपचार और स्वास्थ्य लाभ की नियमित जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 9 बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण राशि प्रभावित परिवारों को राशि उपलब्ध करवाने को कहा है।

सहायता के लिए दल गठित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर छिंदवाड़ा ने नागपुर में उपचार करवा रहे बच्चों की सहायता के लिए तीन दल गठित किए हैं। इन दलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहित एक विशेषज्ञ चिकित्सक को दायित्व दिया गया है। इन दलों द्वारा प्रभावित परिवारों से सतत संपर्क किया जा रहा है जिससे उपचार में किसी तरह की कोई समस्या न हो।

पापा घर ले चलो... पिता के कानों में गूंज रही योजिता की आखिरी आवाज

कोल्ड्रिफ के 'जहर' से 22 दिन तक लड़ी

छिंदवाड़ा (नप्र)। कफ सिरप से एमपी में अब तक 19 बच्चों की मौत हो गई है। यह कहानी उन्हीं में एक बच्ची की है। पापा घर ले चलो... यह योजिता ठाकरे की जिंदगी के आखिरी शब्द थे। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद 22 दिनों तक वह अस्पताल में मौत से लड़ाई लड़ती रही। चार अक्टूबर को जिंदगी की जंग हार गई। पिता सुशांत ठाकरे की आंखों के सामने ही उनकी लाड़ली चल बसी। अब परिवार के सामने है तो सिर्फ उसकी यादें हैं।

प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं पिता – दरअसल, छिंदवाड़ा के बडकुही इलाके में रहने वाले सुशांत ठाकरे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। 8 सितंबर की शाम उनकी दो साल की बेटी योजिता को बुखार आया। सुशांत उसे लेकर डॉ. ठाकुर के पास पहुंचे, लेकिन वे क्लिनिक पर नहीं मिले। मजबूर होकर पास के ही डॉ.प्रवीण सोनी से इलाज कराया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देकर कहा कि चार टाइम दवा देना, बच्ची ठीक हो जाएगी।

सिरप पीने के बाद बिगड़ी तबीयत – कफ सीरप पीने के अगले दिन ही योजिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसने हरे रंग की उल्टियां कीं। सुशांत फिर से डॉक्टर सोनी के पास पहुंचे। इस बार डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की किडनी में इंफेक्शन है, तुरंत नागपुर ले जाओ, यहां इलाज संभव नहीं।

बेटी को लेकर नागपुर गए पिता – सुशांत अपनी बेटी को लेकर तुरंत नागपुर निकल पड़े। जिस अस्पताल का नाम डॉक्टर ने बताया था, वहां पहुंचने पर पता चला कि वहां डायलिसिस की सुविधा नहीं है। रात में ही योजिता को नेल्सन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगले 22 दिनों तक योजिता को 16 बार डायलिसिस पर रखा गया। हर गुजरते दिन के साथ पिता की उम्मीद और अस्पताल का बिल दोनों बढ़ते गए।

पापा घर ले चलो –पिता ने बताया कि हर बार जब वो आंखें खोलती थी तो बस यही कहती थी कि पापा घर ले चलो। और मैं उसे सिर्फ झूठी तसल्ली देता था कि बस बेटा, जल्दी घर चलेंगे।

12-13 लाख का आया खर्च – वहीं,22 दिन के इलाज का 12 से 13 लाख रुपए का खर्च आ गया। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए यह रकम पहाड़ जैसी थी। लेकिन सुशांत ने हार नहीं मानी। परिवार ने एफडी तोड़ दी, बहनों और ससुराल पक्ष ने मदद की।

- **नहीं बचा पाए** – सुशांत ने कहा कि तमाम कोशिशों और दुआओं के बावजूद 4 अक्टूबर की सुबह डॉक्टरों ने कहा कि हमने सब कुछ किया, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है।
- **प्रशासन ने दिया 4 लाख का मुआवजा** – योजिता की मौत के बाद प्रशासन ने परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। पिता सुशांत ने कहा कि इन पैसों से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि जो भी इस गलती के जिम्मेदार हैं- चाहे डॉक्टर हो या दवा कंपनी, उन पर सख्त कार्रवाई हो। ताकि किसी और मासूम की जान न जाए।
- **छिंदवाड़ा में बढ़ रहा बच्चों की मौत का रहस्य** – गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले में बीते एक महीने में कई बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो चुकी है। योजिता की मौत भी उसी सिलसिले की एक कड़ी मानी जा रही है। मेडिकल टीम ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। बताया जा रहा है कि कोल्ड सिरप और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं में मिलावट की आशंका है। प्रशासन की जांच जारी है लेकिन अब तक किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मप्र में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेन्टर

एमपी और फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच हुआ एमओयू

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेन्टर स्थापित करने के लिये कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश और स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच एमओयू हुआ। यह केन्द्र न केवल नवाचार एवं स्मार्ट शहरी समाधानों को प्रोत्साहित करेगा बल्कि वैश्विक स्तर के आयोजनों और निवेश सम्मेलनों की मेजबानी का मंच भी बनेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के इसी साल जुलाई में स्पेन प्रवास के दौरान संस्थान के पदाधिकारियों से चर्चा हुई थी और उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश आमंत्रित किया था।

इस अवसर पर स्पेन के राजदूत श्री जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल तथा फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रिचर्ड जपाटेरो और संस्था के भारत प्रतिनिधि श्री मुकेश अरोरा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से स्पेन के राजदूत श्री जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल ने विस्तार से चर्चा की। यह एमओयू दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक-व्यापारिक रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन, एक्जीबिशन और व्यापार संबंधी संवाद, निवेश सम्मेलनों के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस साझेदारी से वैश्विक निवेशकों ओर हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

मप्र बनायेगा वैश्विक पहचान : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ उद्योग, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में दिल्ली क्षेत्र के विकल्प की दृष्टि से भी आवश्यक अधोसंरचना का विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में इंदौर और भोपाल दो मेट्रापोलिटन क्षेत्र के बाद जबलपुर और ग्वालियर के मेट्रापोलिटन क्षेत्र के विकास की तैयारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्पेन के बार्सिलोना शहर में विकास की विशिष्ट प्लानिंग की गई है। वहां इस वर्ष की गई अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास के साथ विरासत के संरक्षण का संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है। स्पेन के बार्सिलोना जैसे शहर भी प्राचीन वैभव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। मध्यप्रदेश में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बताए मॉडल और बार्सिलोना के संदेश को अपनाया जा रहा है।

दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस में निकला धुआं, शॉर्ट सर्किट से घबराए यात्री

- **चूहों की वजह से रुकी ट्रेन, इंदौर आने वाली एक ट्रेन का मार्ग बदलेगा**

इंदौर (नप्र)। दिल्ली से इंदौर आ रही ट्रेन में मंगलवार सुबह आग लगने की सूचना पर हंगामा मच गया। ट्रेन के बी 4 कोच में धुआं निकलने पर आग लगने के संदेह से यात्री घबरा गए। ऐसे में तुरंत ट्रेन को रोका गया और बोगी खाली की गई। जांच के बाद सामने आया कि चूहों के तार काट दिए जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ था। सुधार होने तक जंगल के बीच ही ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। ट्रेन में फायर अलार्म बजने लगा था,

जिससे यात्री और घबरा गए थे।यह घटना आज सुबह करीब 5.30 बजे कोटा के नजदीक दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (20156) में हुई। यह ट्रेन दिल्ली से रात 11:25 बजे रवाना होती है और अगले दिन 12 बजे इंदौर आती है। ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे जब सभी सो रहे थे तो अचानक धुआं होने से डरकर जाग उठे।हंगामा होने पर ट्रेन को रोका गया। कुछ ही देर में रेलवे स्टाफ बोगी में पहुंचा और सभी यात्रियों को ट्रेन से उतारा। इसके बाद जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं निकलने की बात सामने आई। स्टाफ ने तुरंत सुधार पूरा करने के साथ ही सभी बोगियों की जांच की। स्टाफ ने यात्रियों को बताया कि संभवतः चूहों द्वारा तार काट दिए जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था। सुधार पूरा होने तक ट्रेन जंगल में ही खड़ी रही। सुधार के बाद यात्रियों को दोबारा ट्रेन में बैठाया गया और फिर ट्रेन रवाना हुई। इस बीच यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।